विशेषांक

हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 18 देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 32

धामी सरकार 2.0
सौ दिन 100%

दैनिक न्यूज़ वायरस

विकल्प रहित संकल्प के 100 दिन

tv न्यूज़ वायरस

Watch us on Youtube

संकल्प से सिद्धि के 100 दिन

“ मैं अपने प्रदेश की सवा करोड़ जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं और पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं ।

- पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

“ एक करिश्माई नेता ..... एक युवा नेतृत्व .... एक खुशमिज़ाज़ विधायक और संकल्प से सिद्धि का स्वप्न साकार करते हुए लोकप्रियता के शिखर की और बढ़ते युवा मुख्यमंत्री , नाम है

-पुष्कर सिंह धामी

अब से ठीक सौ दिन पहले 23 मार्च 20222 को देवभूमि में एक चमत्कार हुआ था। यही वो दिन था जब हार कर जीतने वाले जादूगर पुष्कर के हाथों में लगातार दूसरी बार प्रदेश की सत्ता सौंपी गयी थी। उस दिन उत्तराखंड में कई रिकॉर्ड बने थे , कई मिथक टूटे थे। देहरादून का परेड ग्राउंड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में गवाह बन रहा था एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के उदय का जिसको आने वाले कई दशकों तक पहाड़ की सियासत के करिश्माई धाकड़ धामी के नाम पर याद किया जायेगा।

याद कीजिये प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक संबोधन जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। प्रधानमंत्री की इस सोच को सूत्र वाक्य मानकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते 100 दिनों में एक अनुभवी और प्रभावशाली मुख्यमंत्री की तरह सधे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस सौ दिनों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसी कई फैसले कर चुके हैं जो भविष्य में उत्तराखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 100 दिन बृहस्पतिवार को पूरा हो गया। इस दिन एक बार फिर सीएम धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की प्रतिबद्धता जताई है । उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं। जनता ने हम पर जो विश्वास दिखाया, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनायेंगे।’’

मुख्यमंत्री ने 100 दिन के कामकाज का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षानुसार 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिये सभी के सहयोग से काम किया जा रहा है और समृद्ध तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपने हर वादे को पूरा करने में जुटे हैं।

समानता : राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होगी

सख्ती : भ्रष्टाचार के लिए धामी सरकार में कोई स्थान नहीं

सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर आगे बढ़ेंगे

राज्य का भविष्य सुनहरा बनाते ये हैं धामी सरकार के शानदार फ़ैसले -

एक नज़र में

- जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प को बनाई प्राथमिकता
- गुणवत्ता की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का फैसला
- भव्य केदारपुरी के निर्माण के साथ ही श्री बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण में तेज़ी
- धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु ठोस मास्टर प्लान पर तेज़ हुआ कार्य
- गोल्ज्यू सर्किट को विकसित करने के लिए सुनियोजित प्लान बनाने का फैसला
- जनता मिलन कार्यक्रम के ज़रिये लोगों की समस्याएं का हो रहा तेज़ी से निस्तारण
- प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी” को बढ़ावा देने का फैसला
- पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का फैसला
- इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाकर प्रदेश में विकास को दी रफ़्तार
- उत्तराखंड में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं को दी रफ़्तार
- अधिकारियों को प्रत्येक कार्य को सुनियोजित ढंग से करने के लिए निर्देशित
- कुमाऊं में विरासत सर्किट और ऋषिकेश को एक ‘इंटरनेशनल आइकोनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन’ बनाने का फैसला
- गांव-गांव को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए रोड निर्माण को तेज़ करने का फैसला
- चमोली-गोपेश्वर नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बनाने का फैसला
- पत्रकार पेंशन की धनराशि 5000 से बढ़ाकर 8000 करने का फैसला

'विकल्प रहित संकल्प' के साथ धामी सरकार 2.0 का धुआंधार शतक और मुख्यमंत्री धामी का 1 साल बेमिसाल

जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी उस दिन यही वो भरोसा था जो पीएम मोदी ने युवा सीएम धामी के प्रति जताया था। आज सौ दिन के छोटे से कार्यकाल में जिस तरह का धाकड़ नेतृत्व मुख्यमंत्री धामी ने किया है वो बता रहा है कि सुरक्षा से समृद्धि की इस यात्रा को जिस तरह से पहले अल्प कार्यकाल में आगाज़ किया था उस लक्ष्य को अब दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे पांच साल तक जारी रखते हुए उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और सशक्त राज्य बनाने के साथ-साथ देश में विकास के हर मानक पर नम्बर एक बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। आज धामी सरकार की दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के सौ दिनों के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पर गौर करें तो आपको ऐसे कई फैसले मिलेंगे, जो , साहसिक हैं और ऐतिहासिक भी

करिश्माई मुख्यमंत्री धामी के सौ दिन का यह सफर विकास के कई अहम फैसलों और दूरगामी योजनाओं के आगाज़ से भरा रहा है। आइये एक नज़र डालते हैं धामी सरकार के 100 दिन में लिए गए उन बेहतरीन और चुनिंदा फैसलों पर एक नज़र , जिसकी बुनियाद पर आकार ले रहा है आत्मनिर्भर उत्तराखंड -

यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट से किया आगाज़ : धामी सरकार पार्ट 2 का आगाज़ हुआ एक साहसिक निर्णय से जहाँ भाजपा के दृष्टिपत्र में किये गए वादे को पूरा करते हुए सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट के लिए कमेटी बनाने के अपने वादे को पूरा कर दिया है। धामी 2.0 सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी... इसके बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स की एक कमेटी गठित की गयी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है।

प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर फोकस : उत्तराखंड की युवा धामी सरकार की बीते सौ दिनों की उपलब्धि की फेहरिस्त लम्बी है। इस अवधि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखे , उनका फोकस प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने खुद दफ्तरों में छापेमारी कर अफसरों के बीच सख्त संदेश भी दिया। साथ ही कई कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 भी लॉन्च किया तो वहीँ 'NO MEETING DAY' रखने का निर्णय मुख्यमंत्री धामी माना गया जिसमें रचनात्मक प्रयोग करते हुए सन्देश दिया कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने सचिवालय में सप्ताह में एक दिन 'NO MEETING DAY' रखने का निर्णय लिया है, इस दिन अधिकारी आमजन की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान कर रहे हैं।

वृहद स्तर पर चल रहा वेरिफिकेशन का काम : मुख्यमंत्री धामी जानते हैं कि देश बीते कुछ दिनों में किस तरह की चुनौतियों से दो चार हो रहा है। साम्प्रदायिक सौहार्द हो या देवभूमि में शांति सुरक्षा के साथ लॉ एन्ड आर्डर को मजबूत बनाना हो , हर मंच से मुख्यमंत्री ने साफ़ और सख्त सन्देश दिया कि देवभूमि पर्यटक प्रदेश ज़रूर है लेकिन अपराधियों की शरणस्थली हरगिज़ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े प्रदेश को सुरक्षित बनाये रखने और अराजक तत्वों का राज्य में प्रवेश रोकने के लिए उन्होंने प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए जिसके बाद पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर नागरिकों का वेरिफिकेशन किया गया।

चार धाम यात्रा के सफल आयोजन का प्रबंधन किया : कौन यकीन करेगा कि जिस केदारनाथ को जल प्रलय ने तहस नहस कर दिया था उस केदारपुरी को आज प्रधानमंत्री के निर्देशन और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पुनर्निर्माण के बाद दिव्यता और भव्यता के साथ रिकॉर्डतोड़ श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सड़क , परिवहन , स्वास्थ्य और बेहतरीन प्रबंधन से आज विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में एक महीने में ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं। इन ज़िम्मेदारियों के बीच लगातार मुख्य सचिव और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में भव्य व दिव्य केदारपुरी के साथ साथ मास्टर प्लान के अंतर्गत बद्रीनाथ धाम में विकास कार्य हो रहे हैं। मकसद है कि पर्यटकों और धार्मिक यात्रियों को आने वाले दिनों में बेहद सुगम और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था दी जा सके। मौजूदा चार धाम यात्रा में धामी सरकार ने अभूतपूर्व इंतज़ाम करते हुए वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को चार धाम यात्रा व्यवस्था की ज़िम्मेदारी दी है। जिसका नतीज़ा है कि आज उत्तराखंड को भारी राजस्व के साथ स्टेट की ब्रांडिंग में भी काफी मुनाफ़ा हो रहा है।

मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत: कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिये मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत जल्द होने वाली है... मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिये सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण का रोडमैप तैयार किया जा

रहा है। वहीँ शैव सर्किट और महाभारत सर्किट पर भी धामी सरकार ने अहम योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है।

वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया ऐतिहासिक फैसला: मुख्यमंत्री धामी ने पहले सौ दिन में जनहित से जुड़े कई कल्याणकारी फैसले भी लिए हैं... जिसमें उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा.. इतना ही नहीं वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदत्त दर 1200 रुपये प्रतिमाह में 200 रुपये की वृद्धि की गई है... अब इनमें प्रतिमाह 1400 रुपये पेंशन प्राप्त होगी... स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हजारों पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। बीते दिनों धामी सरकार ने पत्रकार पेंशन की धनराशि 5000 से बढ़ाकर 8000 करने की घोषणा की है।

फोरलेन हाईवे और मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण: वहीं, बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी मुख्यमंत्री धामी लगातार ध्यान दे रहे हैं। उनकी मजबूत पहल पर केंद्र सरकार ने एनएच-72 के पांवटा साहिब-बल्लूपुर (देहरादून) खण्ड के उन्नयन और फोर लेन के निर्माण के लिये 1093.01 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिये पर्वत माला परियोजना का खाका तैयार कर लिया गया है।

Pushkar Singh Dhami
Chief Minister,
Uttarakhand
Satpal Maharaj
PWD Minister,
Uttarakhand
VT-UAB
Resident Commissioner Office Uttarakhand
The creation of BRIDCUL stands as testimony to the Government of Uttarakhand's commitment to provide a strong, credible and proactive institutional mechanism for leveraging private sector initiatives for Infrastructure Development.
BRIDCUL
सर्वत्र विकासाय :
बिडकुल
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

दैनिक न्यूज़ वायरस **विकास के 100 दिन**

यही संकल्प यही इरादा, पूरा करेंगे हर वादा

सतपाल महाराज

लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, संस्कृति, धर्मस्व , ग्रामीण निर्माण एवं जलागम प्रबंधन मंत्री

उत्तराखंड सरकार में कद्दावर और प्रभावशाली मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का नाम पहले आता है। महाराज के प्रभाव का अंदाज़ा उनके पास मौजूद भारी भरकम विभागों की फेरहिस्त से हो जाता है । मंत्री महाराज उत्तराखंड की चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक है। विश्व स्तर पर अपनी दार्शनिक विचारधारा से आध्यात्मिक गुरु की छवि बनाने वाले धामी सरकार में पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड की राजनीति में कद्दावर नेता है। पहाड़ की राजनीति से इतर उनकी एक पहचान संत के रूप में भी है। दुनिया के तमाम देशों में उनके करोड़ों भक्त हैं। छात्र जीवन से ही उनकी दार्शनिक छवि रही है और आज न सिर्फ सियासत में बल्कि आध्यात्मिक की दुनिया में भी एक प्रतिष्ठित शख्सियत है सतपाल महाराज।

प्रदेश की मौजूदा पुष्कर सरकार में इन्हे सबसे प्रभावशाली मंत्री माना जाता है। यही नहीं अपनी तेजतर्रार छवि , सख्त कार्यशैली और अनुभवी कार्य क्षमता की वजह से लोक निर्माण मंत्री महाराज अक्सर चर्चाओं में भी आ जाते है क्योंकि कभी ये अचानक विभागों में निरीक्षण करने पहुंच जाते है तो कभी विभागीय मीटिंग में अफसरों की लापरवाही पर बरस पड़ते हैं। बावजूद इसके सतपाल महाराज ने बीते सौ दिनों में अपने सभी महकमों में बेहतरीन योजनाए बनाई और प्रदेश हित में अनेक फैसले किये है जो आने वाले सालों में उत्तराखंड की सुनहरी तकदीर की बुनियाद बनेगा। आइये नज़र डालते है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के 100 दिन के कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण फैसलों और उपलब्धियों पर -

- लोक निर्माण विभाग / पर्यटन / संस्कृति विभाग की योजनाओं में आई तेजी , फाइलों ने पकड़ी रफ्तार
- बीते 100 दिनों में PWD की कार्यशैली और जवाबदेही को बनाया प्रभावीसभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश
- बिना वित्तीय स्वीकृति के किसी कार्य को अप्रूव ना करने का सख्त निर्देश किया जारी
- मॉनसून सीजन में सड़कों के नुकसान को रोकने के लिए नालियों का निर्माण
- स्मार्ट सिटी, शहरी विकास विभाग, पर्यटन, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग का बना तालमेल
- प्रदेश भर में तकरीबन 600 पुल का सेफ्टी ऑडिट कराने का दिया आदेश
- जहां रोपवे संभव नहीं है, वहां पर फर्नीकुलर रेल योजना पर हो रहा कार्य
- फ्लोटिंग हाउस के निर्माण , होमस्टे का व्यापक प्रचार प्रसार , विंटर टूरिज्म को बढ़ावा स्टाइल सुपर मॉडल पर फोकस
- त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का फैसला
- सतपुली एवं स्यूंसी का कॉन्सेप्ट नोट तैयार कर सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश
- मानसून से पूर्व सभी नदियों की ड्रेजिंग करवाने के निर्देश
- बाढ़ चौकियां स्थापित कर लोगों को बाढ़ संबंधित जानकारी की पूर्व सूचना देने का आदेश
- लोक निर्माण विभाग को सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित करने का आदेश संस्कृति विभाग के गढ़ी कैंट में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम को शानदार स्वरूप देने के निर्देश
- उत्तराखंड में ललित कला साहित्य कला संगीत नाट्य कला खोलने का प्रस्ताव तैयार आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गढ़वाली, कुमाऊंनी एवं जौनसारी गीतों को तैयार कराने का आदेश सर्वश्रेष्ठ गीतों के लिए प्रथम पुरस्कार ₹2 लाख, द्वितीय पुरस्कार ₹1 लाख और तृतीय पुरस्कार ₹50 हजार गीतकारों को देने का आदेश सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आदेश
- बांध प्रभावित 415 विस्थापितों के पुनर्वास के लिए धनराशि वितरण के आदेश
- टिहरी झील के किनारे तार बाड़ करने के लिए भी निर्देश

चार धाम यात्रा की अभूतपूर्व कामयाबी का मास्टर प्लान हुआ सफल

दो साल के बाद आयोजित हो रही देवभूमि की आर्थिकी के सबसे बड़े आयोजन चार धाम यात्रा को सुखद , सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी और पर्यटन मंत्री महाराज ने एक एक विभाग की जिम्मेदारी तय करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की। यात्रा मार्गों को सुगम बनाया और स्थानीय व्यापारियों को सभी ज़रूरी मदद पहुंचाई। जिसकी वजह से देश दुनिया से आ रहे तीर्थयात्रियों की संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पर्यटन मंत्री महाराज के निर्देश पर चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों और यात्रा को सुगम बनाने वाले बेजुबान प्राणियों के लिए स्वास्थ्य परिक्षण की व्यवस्था देते हुए खान पान और गर्म पानी उपलब्ध कराये गए। केदारनाथ और बद्रीनाथ

दैनिक न्यूज़ वायरस

में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी आई और यात्रा मार्गों को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण भी किया गया है। जिसकी वजह से आज पर्यटन प्रदेश में आने वाले यात्रियों का सफर सुगम और सुरक्षित बन गया है। केदारनाथ धाम मार्ग में विभिन्न जगहों पर भारत के वीर सपूत और देश के प्रथम रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के नाम के सेल्फी प्वाइंट बनाने की घोषणा भी सैन्य धाम की पहचान को आगे बढ़ाने में मंत्री सतपाल महाराज का एक बड़ा फैसला है।

कांवड़ यात्रा पर बरसेंगे आसमान से फूल :

उत्तराखंड में हरिद्वार सहित अनेक ऐसे शिव धाम है जहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िये पहुँचते है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिव भक्त है ऐसे में इस बार कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास इंतजाम किये जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री महाराज ने बताया है किकांवड़ यात्रा को सफल रूप से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। देवभूमि में कांवड़ यात्रियों के लिए धामी सरकार ने खास तैयारी भी की है। बीते साल की तरह इस बार भी यात्रियों का स्वागत हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा द्वारा की जाएगी।

हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देगा पर्यटन को नई उड़ान

धामी सरकार के सौ दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है प्रदेश की ब्रांडिंग का बढ़ता दायरा .. देवभूमि की करीब दो साल बाद कोरोना से सामान्य हुई स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से उत्तराखण्ड में सभी पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। तीन मई से शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में रिकॉर्डतोड़ तीर्थयात्रियों की संख्या उत्तराखंड सरकार की कामयाब तैयारियों की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। वहीं अब पर्यटन मंत्री महाराज ने उत्तरकाशी जिले में गरतांग गली का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है कि भारत-तिब्बत व्यापार की गवाह रही नेलांग घाटी में स्थित ऐतिहासिक गरतांग गली की सीढ़ियों का देश दुनिया के पर्यटक दीदार कर रहे हैं।इसी के साथ उन्होंने हर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंच से बीटल्स आश्रम और चोपता जैसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहाड़ों में हरिद्वार में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है और पर्यटकों के बीच होमस्टे और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की भी मैंने विस्तार से जानकारी दी।राज्य के संपूर्ण विकास हेतु हम संकल्पबद्ध है।

पर्यटन से मिलेगा रोज़गार - योजनाओं की है भरमार -

बेरोजगारी को खत्म करना भी उत्तराखंड सरकार का बड़ा लक्ष्य है। इसीलिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की कोशिश है कि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्व रोजगार से जोड़ने के लिए योजनाएं बनायी जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्यटन विभाग की ओर से वीर चन्द्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, उत्तराखंड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना, ट्रेकिंग ट्रक्शन सेंटर , होम स्टे अनुदान योजना सहित तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आईपीई ग्लोबल कंसल्टेंसी के माध्यम से उत्तराखंड पर्यटन विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 नवीन थीम बेस्ट डेस्टिनेशन के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हरिद्वार में दीनदयाल पार्किंग से चंडी देवी तक रोपवे निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। हरिद्वार में रोपवे बन जाने के बाद चंडी देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे सेवा, राज्य गठन के बाद पहली महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना है जिसका सफलतापूर्वक निर्माण राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है।

होम स्टे की सफल योजना से जुड़ेंगे खाली पड़े स्कूल

होम स्टे योजना की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में की है। पहाड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ रोज़गार के मौके उपलब्ध कराने में उत्तराखड के पर्यटन मंत्री महाराज का ये विजन हिट ही नहीं सुपरहिट साबित हुआ है। पर्यटकों के बीच होम स्टे और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने की दिशा मे दीनदयाल होमस्टे योजना के तहत स्थानीय लोगों को होमस्टे स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो वहीं अब राज्य में खाली पड़े स्कूलों को होम स्टे में बदलने का प्रयास है। ट्रेकिंग के रूट पर आने वाले इन खाली पड़े स्कूलों को होम स्टे में बदले जाने से राज्य में पर्यटन को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

सड़क निर्माण और बाढ़ नियंत्रण पर ज़ोर -

उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से बांध से संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए डैमों की सुरक्षा पर योजना बना रही है। जिसके लिए राष्ट्रीय और राज्य लेवल पर गठित कमेटी की गतिविधियों पर मंथन किया जा रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना को तेजी से धरातल पर उतारते हुए उच्च गुणवत्ता की सड़कें तैयार की जा रही है। कार्य संस्कृति को पारदर्शी बनाने के साथ साथ लापरवाह अधिकारीयों को सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। यही वजह है कि विकास योजनाओं को रफ़्तार मिली है और पिछले सौ दिनों में अभूतपूर्व निर्माण कार्य कराये गए है। हरिद्वार में कनखल, भोगपुर, गंगादासपुर होकर बालावाली तक गंगा के पुस्तों के समानांतर बनने वाली सड़क प्रथम चरण के कार्यों की शुरुआत हो गई है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत इस सड़क के प्रथम चरण के कार्यों जैसे भूमि की व्यवस्था, सर्वेक्षण, डीपीआर गठन के लिए 32.50 किलोमीटर लंबाई के लिए 97.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।फीका नदी एवं ढेला नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्व में भी कराए जाते रहे है, जिनसे इन नदियों के किनारे स्थित कृषि भूमि और आवासीय बस्ती को सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। इसके अतिरिक्त समय समय पर आवश्यकतानुसार इन नदियों के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाएं गठित की गयी है।

पंचायतों को मजबूती देने के लिए एसीआर का दिया अधिकार

पंचायतीराज मंत्री के तौर पर पहले सौ दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर सतपाल महाराज का वो एलान है जिसमें उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख बीडीओ की एसीआर लिखा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए दीनदयाल मिनी सचिवालय का पंचायतों में गठन होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश काम दीनदयाल मिनी सचिवालय में भी हो सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन समेत कई दस्तावेज दीनदयाल मिनी सचिवालय में ही बनेंगे।

उत्तराखंड बन रहा फिल्म शूटिंग का पसंदीदा डेस्टिनेशन

उत्तराखंड में फिल्म नीति के तहत कई आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य में अपनी फिल्म परियोजनाओं के लिए आने के इच्छुक निर्माताओं और निवेशकों के लिए अधिक से अधिक बुनियादी ढांचे को सुविधाजनक बनाने और विकसित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुंबई में स्थापित बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़े निर्माता निर्देशक लगातार उत्तराखंड की वादियों में बड़े स्टार वाली फिल्में शूट कर रहे हैं और खुद पर्यटन विभाग लगातार फिल्म जगत के दिगज हस्तियों के साथ मीटिंग्स और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जिसका नतीजा है कि बीते कुछ ही महीनों में तमाम बड़े अभिनेता - अभिनेत्रियां उत्तराखंड पहुंची हैं। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि धामी सरकार का उद्देश्य फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखंड को एक आदर्श गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है ऐसे में उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड में फिल्मकारों को आमंत्रित करने का लगातार प्रयास कर रही है।

इस दिशा में फिल्मकारों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई दोराय नहीं कि पर्यटन की दृष्टि से सबकी पसंद उत्तराखंड अब फिल्मों की शूटिंग में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी संख्या मेंफिल्मकार उत्तराखंड में निवेश करेंगे।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस

देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022

पहाड़ों में रोपवे, टनल, भवनों और पुलों का निर्माण ब्रिडकुल की कामयाबी का नमूना है

भूमि उत्तराखंड एक अद्भुत पर्यटन प्रदेश है , एक ऐसी भूमि है जहां देश प्रदेश के सैलानी साल भर यहां आते हैं और कुदरत के नजारों को निहारते हैं। देश के पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड की अपनी अहमियत है , अपनी गरिमा है। यही वजह है कि पुष्कर राज में उत्तराखंड के विकास को रफ़्तार देने के लिए विकल्प रहित संकल्प को साकार किया जा रहा है।

राज्य के युवा धामी सरकार के कंधों पर है अतिथि देवो भव की भावना को सफल और साकार करने की बड़ी जिम्मेदारी ... यही वजह है कि सरकार के सभी अंग और महत्वपूर्ण विभाग मिलकर पर्यटन प्रदेश में सुखद और सुगम यात्रा के लिए सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार के अभिन्न और महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाओं में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है ब्रिज रोपवे टनल एन्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलोपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड यानि ब्रिडकुल

ब्रिडकुल एक ऐसी संस्था है जिस के कंधों पर प्रदेश में विकास की गाड़ी को सरपट दौड़ने की जिम्मेदारी है। लिहाजा विभाग का हर कर्मचारी और हर अधिकारी अपने राज्य की ब्रांडिंग और मजबूत बिल्डिंग निर्माण में बेहद गंभीर और पारदर्शी जिम्मेदारी निभा रहा है । प्रदेश के लोक निर्माण विभाग पर्यटन और पंचायती राज का महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे अनुभवी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का विजन है कि निर्माण और अवस्थापना के क्षेत्र में उत्तराखंड का बहुमुखी विकास हो , जिससे यहां आने वाले सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिकी और समृद्धि के रास्ते को संवारा जा सके। बीते 100 दिनों की उपलब्धियों की बात करें तो लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य में चल रहे निर्माण कार्यो को तेजी से संपन्न करने के निर्देश दिए तो वही विभाग की जवाबदेही तय करते हुए पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रहित कार्य प्रणाली को विकसित करने का भी निर्देश दिया।

उत्तराखंड सरकार की बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाओं को तय मानक और समय से साकार करते हुए प्रदेश में ब्रिडकुल आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जो प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर को संभालने में पहली पंक्ति में खड़ा है।

2022 में जब से प्रदेश में युवा पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कामकाज संभाला है पहले दिन से लेकर पहले 100 दिन तक राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को साधने के लिए हर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश की है। इसकी वजह है धामी सरकार का पारदर्शिता पर जोर और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज का तय समय में जवाबदेही के साथ योजनाओं के विकास की रफ्तार पर सख्त नजर ... प्रदेश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने और विकास के इसी विजन को साकार करने में ब्रिडकुल लगातार अपनी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ संपन्न कर रहा है

प्रदेश में सरकारी स्कूल , अस्पताल , भवन , छात्रावास , विभागीय कार्यालय और पुलों के साथ तमाम अवस्थापना को मजबूती और खूबसूरती के साथ साकार कर रहा है ब्रिडकुल , भला कौन भूल सकता है पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयर स्ट्रिप का वह मजबूत निर्माण जिसे संभव कर दिखाया था ब्रिडकुल ने

आईएचएम देहरादून के गर्ल्स हॉस्टल की खूबसूरत इमारत हो या सूचना का अधिकार आयोग का आलीशान भवन या राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की इमारत यही नहीं अगर आपको ब्रिडकुल की काबिलियत को करीब से देखना है तो देहरादून विधानसभा की एनेक्सी बिल्डिंग को जरूर देखिए जो बताता है कि ब्रिडकुल के अनुभवी अधिकारियों की काबिलियत ने किस तरह से राज्य सरकार के सपनों को आकार दिया है उन्हें साकार किया है

अपनी काबिलियत और पारदर्शी निर्माण कार्यों के लिए अनेकों उपलब्धियां हासिल करते हुए आज ब्रिडकुल ने जिस तरह से निर्माण के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर पहाड़ों में रोप वे , टनल , और पुलों का निर्माण ब्रिडकुल की टीम के द्वारा किया जा रहा है।

टिहरी जिले के नैनबाग में डिग्री कॉलेज का निर्माण और बेहद चुनौतियों भरे रुद्रप्रयाग जिले में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों का आधार तैयार करना हो , अगस्त मुनि इलाके में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अनेक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का निर्माण बताता है कि ब्रिडकुल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्तराखंड का एक प्रतिष्ठित ब्रांड है और जिसके कंधों पर उत्तराखंड में निर्माण और विकास की मजबूत जिम्मेदारी है। सितारगंज में सितारगंज डिग्री कॉलेज , जुवेनाइल एंड माइनर जेल , महिला जेल , बाजपुर में डिग्री कॉलेज की साइंस बिल्डिंग और बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कर ब्रिडकुल ने अपने हुनर का परिचय दिया है। अल्मोड़ा में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट , सोमेश्वर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और प्रदेश के तमाम इलाकों में पॉलिटेक्निक और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने में भी ब्रिडकुल ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। अगर आपको ब्रिडकुल की भव्य इमारतों का दीदार करना है तो आइए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री भरसार की भव्य इमारत को देखकर अनुभवी अधिकारियों और मेहनतकश इंजीनियरों के काबिलियत का नमूना नज़र आ जायेगा।

दरअसल इस सफलता के पीछे है ब्रिडकुल के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिकारियों का वो वर्ग जिनके पीछे है लंबा प्रशासनिक और फील्ड का अनुभव ,इंडियन आर्मी , पीडब्ल्यूडी , रेलवे एनएचआई और कारपोरेट के वरिष्ठ पूर्व अधिकारियों के समावेश से बना है ब्रिडकुल का ढांचा। यही वजह है कि ब्रिडकुल को अपने हर प्रोजेक्ट में अलग-अलग क्षेत्रों के कुशल विशेषज्ञों का अनुभव मिलता है और तब जाकर साकार होता है उत्तराखंड सरकार का सपना और जिसका शिल्पकार है ब्रिडकुल

कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों और कुशल प्रबंधकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर कामयाब कदम बढ़ा रहा है ब्रिडकुल जहाँ अनुभवी इंजीनियरों की टीम है तो वही प्रयोग के लिए लैब्स की सुविधा है जहां अधिकारी और कर्मचारी अपने मिशन को पूरी लगन और निष्ठा के साथ साकार करने में जुटे हैं। आज ब्रिडकुल अपने शानदार उपलब्धियों की इमारत पर नए कीर्तिमान और नए आयाम स्थापित कर रहा है।

हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस

देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022

वन मंत्रालय ने लिए अभूतपूर्व फैसले, पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता : सुबोध उनियाल (वन मंत्री)

उत्तराखंड की पुष्कर सरकार ने अपने शानदार 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। अपने कड़े प्रशासनिक प्रबंधन और कल्याणकारी फैसलों की वजह से धामी सरकार ने प्रचंड बहुमत को सार्थक साबित करने में भी कामयाबी हासिल की है। देवभूमि को वनों और प्राकृतिक सौंदर्य की धरती कहते हैं ऐसे में उत्तराखंड वन विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियां बेहद खास और अहम हो जाती है आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल प्रदेश के वन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं ऐसे में अनुभव और बेहतरीन प्रशासनिक प्रबंधन के माहिर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते 100 दिनों में केंद्र सरकार के विजन और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर कामयाबी के साथ विभाग को आगे बढ़ाया है फिर वह चाहे वनों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को खत्म करना हो या जंगलों में लग रही आग पर काबू करते हुए एक प्रभावशाली योजना तैयार करनी है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पहाड़ के हर जिले से लेकर मैदान के हर शहर तक वन महकमे को मजबूती प्रदान करते हुए पारदर्शिता के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने में अधिकारियों को तमाम बड़े दीजिए जिन्हें हम इंसानों की उपलब्धियों में शामिल कर रहे हैं

सुबोध उनियाल, वन मंत्री बोले, विकास परक योजनाओं में वन विभाग किसी भी प्रकार की अड़चनें पैदा नहीं करेगा... हर गांव को सड़क की जरूरत है... वन संरक्षण और रोज़गारपरक योजनाओं के क्षेत्र में भी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है... वनों को बचाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकार गांव स्तर पर जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाने की

दिशा में काम कर रही है।

2022 विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ संकल्प से सिद्धि का मंत्र लेकर युवा पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी संभाली और उनके तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के लिए बेहतरीन योजनाएं और जनहितकारी फैसले लिए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वन विभाग के 100 दिनों के लेखा-जोखा की , जहां धामी सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल की उपलब्धियों पर हम नजर डाल रहे हैं।

- ❖ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वन क्षेत्र में लगभग 14 हज़ार 300 हेक्टेयर में 1. 25 करोड़ पौधों के रोपण हेतु समस्त आवश्यक कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है
- ❖ राज्य के टूरिज्म डेस्टिनेशन को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के दोनों ओर लगभग 36 किलोमीटर में वृक्षारोपण कार्य हुआ
- ❖ बायो फेंसिंग यानी जैविक घेरबाड़ - जंगली जानवरों विशेषकर जंगली सूअर और जंगली हाथी से फसल की सुरक्षा के लिए परंपरागत पत्थरों की दीवार के विकल्प के रूप में वानस्पतिक विधि से जैविक घेरबाड़ यानी बायोफेन्सिंग का निर्णय
- ❖ प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत चार धाम यात्रा के विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित कर हटाया गया
- ❖ ईको टूरिज्म एवं अन्य वन एवं वन्य जीव आधारित गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान किए गए
- ❖ वनाग्नि प्रबंधन में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए को वनाग्नि के नुकसान को अत्यधिक सीमित किया गया
- ❖ अनुसंधान औषधीय एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं संकटापन्न प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त पौध / रोपण सामग्री की आपूर्ति तथा विभिन्न पादप समूहों , ऑर्किड , फन , बांस रिंगाल और लाइकेन के संरक्षण एवं अनुसंधान में उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 26 जैव विविधता संरक्षण स्थल स्थापित किए गए
- ❖ देश का पहला देवबन चकराता , क्रिप्टोगेमिक गार्डन व सडियाताल नैनीताल मॉस गार्डन
- फॉरैस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत , अनुसंधान रेंज रानीखेत
- ❖ चमोली के मंडल में आर्केड संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र तथा माणा में उच्च स्तरीय हर्बल गार्डन
- ❖ मुंस्यारी पिथौरागढ़ में बुरांश संरक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र , लाइकेन गार्डन , संकटापन्न प्रजाति संरक्षण स्थल , चौकोडी में उच्च स्तरीय औरबोरटम , लुंगती में आर्केड संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र
- ❖ ष्टवर्ग प्रदर्शन व संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी
- ❖ बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी नैनीताल में
- ❖ लाल कुआं नैनीताल में फाइकस गार्डन , जल स्वास्थ्य वाटिका , दशमूल गार्डन , सगंध प्रजाति संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र
- ❖ ज्योलीकोट नैनीताल में शिवालिक आरबोरेटम
- ❖ रानीखेत के कालिका में फर्न संरक्षण व प्रदर्शन क्षेत्र , द्वारसी में घास प्रजाति संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र तथा हिमालयी मसालों का प्रदर्शन केंद्र
- ❖ श्यामपुर हरिद्वार में प्रकृति ध्यान केंद्र
- ❖ कैंपा योजना के अंतर्गत प्रदेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य वृक्षारोपण ,सूख रहे जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन , वनाग्नि प्रबंधन हेतु सेंटर की स्थापना , उत्तरकाशी में देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना , इको टूरिज्म के विकास
- ❖ जैव विविधता संरक्षण हेतु वाकिंग ट्रेल्स , वन पंचायतों के माध्यम से पंचायती वनों में वानिकी कार्य , केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत विभिन्न उपचार कार्य आदि की योजना तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई है...

दैनिक न्यूज़ वायरस **विकास के 100 दिन**

विकास मेरा जूनून , जनसेवा मेरा संकल्प : सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

उत्तराखंड की जनता ने 2022 में जिस उम्मीद के साथ दोबारा धामी सरकार पर भरोसा जताया है उस पर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री आगे बढ़ रहे हैं। बीते 100 दिनों में सरकार ने सख्त अनुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि प्रदेश के अनुभवी मिनिस्टर और नरेंद्र नगर से वरिष्ठ विधायक सुबोध उनियाल ने कह दिया है कि भ्रष्ट अधिकारी वीआरएस ले लें क्योंकि धामी सरकार विभागों में सुधार की प्रक्रिया को सख्ती से आगे बढ़ा रही है , जिसमें लापरवाह और करप्ट अफसरों के बचने की कोई गुंजाईश नहीं रहेगी। इस दिशा में उन्होंने सख्त निर्णय भी लिए हैं। वहीं चार धाम यात्रा में बदरीनाथ धाम के प्रभारी के तौर पर भी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बेहतरीन प्रबंधन किया है जिसमें उनके लम्बे अनुभव और कुशल प्रशासनिक क्षमता नज़र आती है। वहीं वन विभाग को प्रभावी बनाने के लिए बीते सौ दिनों में बड़े पैमाने पर बैठकें , निरीक्षण और स्थलीय दौरे कर प्रगति की रफ़्तार को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

आइये कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के 100 दिनों के विभागीय निर्णयों/उपलब्धियों पर डालते हैं एक नज़र

- विभाग की कमान संभालते ही भ्रष्ट अफसरों पर कार्यवाही का लिया सख्त फैसला
- विभागों को भ्रष्टाचार मुक्त और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए किये सख्त फैसले
- प्रदेश में वन कानूनों की आड़ में लोगों का उत्पीड़न रोकने के दिए आदेश
- वन विभाग के लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर की गयी सख्त कार्यवाही
- जांच के बाद 2 आईएफएस अधिकारियों को किया निलंबित, एक को किया अटैच
- जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाने का फैसला
- रसूखदारों लोगों के अतिक्रमण से कब्जाई गई वन भूमि को मुक्त कराने की पहल
- तकनीकी शिक्षा विभाग में नियमित नियुक्तियां करने का फैसला
- तकनीकी शिक्षा विभाग में सुधार के हर संभव प्रयास के दिए आदेश
- उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक में लिए गए बड़े निर्णय
- सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धाम एवं गोविंदघाट से श्री हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए वन भूमि हस्तांतरण का फैसला
- तकनीकी शिक्षा में व्यापक सुधार को लेकर तकनीकी शिक्षा में सुधार का फैसला
- राजकीय भेड़ एवं बकरी अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला का निर्माण
- वन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं को प्रभावी बनाने पर ज़ोर
- नरेंद्रनगर विकासखंड कीग्राम सभाओं में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 25 लाख रुपए की स्वीकृति
- प्रदेश में जायका परियोजना की अवधि दो वर्ष बढ़ने से योजनाओं का फायदा
- उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन (जायका) परियोजना की प्रगति
- वन क्षेत्रों में भूस्खलन की रोकथामआजीविका विकास, जल व मृदा संरक्षण जैसे कार्य में सफलता
- जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को अधिक महत्व देने की योजना को प्रभावी बनाया
- आजीविका विकास के मद्देनजर पौधालयों की स्थापना करने का फैसला
- वन पंचायतों में जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्यों से कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था में सुधार
- टिहरी जिले के काणाताल में कौड़िया इको ट्रेल का शुभारंभ
- नरेंद्र नगर में केन्द्रीय विद्यालयके लिए स्वीकृत भूमि पर कार्य शुरू
- कार्बेट नेशनल पार्क केविभागीय कार्य-कलापों में पारदर्शिता और योजनाओं पर मंथन
- राज्यांतर्गत टेरिटोरियल व नॉन-टेरिटोरियल वन पर कार्य योजना
- ढिकाला एवं कालागढ़ रेंज का में सुविधाओं और व्यवस्था बढ़ाने का आदेश
- पिथौरागढ़ में पर्यटन गन्तव्य केंद्र विकसित किये जाने हेतु ट्यूलिप लैंडस्केप विकसित किये जाने का फैसलाप्रदेश में वनाग्नि और अतिक्रमण की रोकथाम के लिए लिए गए अहम और कारगर फैसले

देवभूमि उत्तराखंड का विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली ही हमारा लक्ष्य है। जिसके लिए दिन रात कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाया जा रहा है। बीते सौ दिनों में हमने हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। धामी सरकार ने इस दौरान कई विकास योजनाएं संचालित की हैं , जिसका लाभ सभी को मिल रहा है।

-सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

वन मंत्रालय ने लिए अभूतपूर्व फैसले पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सुबोध उनियाल
वन मंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखंड की पुष्कर सरकार ने अपने शानदार 100 दिन के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। अपने कड़े प्रशासनिक प्रबंधन और कल्याणकारी फैसलों की वजह से धामी सरकार ने प्रचंड बहुमत को सार्थक साबित करने में भी कामयाबी हासिल की है। देवभूमि को वनों और प्राकृतिक सौंदर्य की धरती कहते हैं ऐसे में उत्तराखंड वन विभाग के 100 दिनों की उपलब्धियां बेहद खास और अहम हो जाती है आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल प्रदेश के वन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं ऐसे में अनुभव और बेहतरीन प्रशासनिक प्रबंधन के माहिर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते 100 दिनों में केंद्र सरकार के विजन और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए संकल्प से सिद्धि की ओर कामयाबी के साथ विभाग को आगे बढ़ाया है फिर वह चाहे वनों में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को खत्म करना हो या जंगलों में लग रही आग पर काबू करते हुए एक प्रभावशाली योजना तैयार करनी है कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पहाड़ के हर जिले से लेकर मैदान के हर शहर तक वन महकमे को मजबूती प्रदान करते हुए पारदर्शिता के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने में अधिकारियों को तमाम बड़े दीजिए जिन्हें हम इंसानों की उपलब्धियों में शामिल कर रहे हैं।

विकास परक योजनाओं में वन विभाग किसी भी प्रकार की अड़चनें पैदा नहीं करेगा... हर गांव को सड़क की जरूरत है... वन संरक्षण और रोजगारपरक योजनाओं के क्षेत्र में भी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है... वनों को बचाना आवश्यक है, जिसके लिए सरकार गांव स्तर पर जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाने की दिशा में काम कर रही है सुबोध उनियाल, वन मंत्री

2022 विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ संकल्प से सिद्धि का मंत्र लेकर युवा पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी संभाली और उनके तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के लिए बेहतरीन योजनाएं और जनहितकारी फैसले लिए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड वन विभाग के 100 दिनों के लेखा-जोखा की , जहां धामी सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल की उपलब्धियों पर हम नजर डाल रहे हैं।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वन क्षेत्र में लगभग 14 हजार 300 हेक्टेयर में 1. 25 करोड़ पौधों के रोपण हेतु समस्त आवश्यक कार्यों को अंतिम रूप दिया गया है
राज्य के टूरिज्म डेस्टिनेशन को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के दोनों ओर लगभग 36 किलोमीटर में वृक्षारोपण कार्य हुआ
बायो फेंसिंग यानी जैविक घेरबाड़ – जंगली जानवरों विशेषकर जंगली सूअर और जंगली हाथी से फसल की सुरक्षा के लिए परंपरागत पत्थरों की दीवार के विकल्प के रूप में वानस्पतिक विधि से जैविक घेरबाड़ यानी बायोफेन्सिंग का निर्णय
प्लास्टिक मुक्त अभियान के अंतर्गत चार धाम यात्रा के विभिन्न स्थानों पर प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित कर हटाया गया
ईको टूरिज्म एवं अन्य वन एवं वन्य जीव आधारित गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान किए गए
वनाग्नि प्रबंधन में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए को वनाग्नि के नुकसान को अत्यधिक सीमित किया गया
अनुसंधान औषधीय एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं संकटापन्न प्रजातियों के गुणवत्ता युक्त पौध व रोपण सामग्री की आपूर्ति तथा विभिन्न पादप समूहों, अ०र्किड, फन, बांस रिंगाल और लाइकेन के संरक्षण एवं अनुसंधान में उत्तराखंड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 26 जैव विविधता संरक्षण स्थल स्थापित किए गए
देश का पहला देवबन चकराता, क्रिप्टोगेमिक गार्डन व सडियाताल नैनीताल म०स गार्डन
फ०रेस्ट हीलिंग सेंटर रानीखेत, अनुसंधान रेंज रानीखेत
चमोली के मंडल में आर्केड संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र तथा माणा में उच्च स्तरीय हर्बल गार्डन
मुंस्यारी पिथौरागढ़ में बुरांश संरक्षण एवं प्रदर्शन क्षेत्र, लाइकेन गार्डन, संकटापन्न प्रजाति संरक्षण स्थल, चौकोडी में उच्च स्तरीय औरबोरटम, लुंगती में आर्केड संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र
अष्टवर्ग प्रदर्शन व संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी
बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी नैनीताल में लाल कुआं नैनीताल में फाइकस गार्डन, जल स्वास्थ्य वाटिका, दशमूल गार्डन, सगंध प्रजाति संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र, ज्योलीकोट नैनीताल में शिवालिक आरबोरेटम रानीखेत के कालिका में फर्न संरक्षण व प्रदर्शन क्षेत्र, द्वारसी में घास प्रजाति संरक्षण व प्रदर्शन केंद्र तथा हिमालयी मसालों का प्रदर्शन केंद्र
श्यामपुर हरिद्वार में प्रकृति ध्यान केंद्र
कैंपा योजना के अंतर्गत प्रदेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य वृक्षारोपण,सूख रहे जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वनाग्नि प्रबंधन हेतु सेंटर की स्थापना, उत्तरकाशी में देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना, इको टूरिज्म के विकास
जैव विविधता संरक्षण हेतु वाकिंग ट्रेल्स, वन पंचायतों के माध्यम से पंचायती वनों में वानिकी कार्य, केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के अंतर्गत विभिन्न उपचार कार्य आदि की योजना तैयार कर भारत सरकार को भेजी गई है...

उत्तराखण्ड वन विभाग

उत्तराखंड वन विभाग, देहरादून

HQ Address: 85, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand, India. Email: itgc-forest-uk@nic.in

दैनिक न्यूज़ वायरस विकास के 100 दिन

देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन ने पकड़ी रफ्तार, जल्द खत्म होगा आपका इंतज़ार

भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है देहरादून , सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को संजोये उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी देहरादून को मिनी हिन्दुस्तान भी कहते हैं। हिमालय और शिवालिक पर्वत क्षेत्र की तलहटी में स्थित दून शहर को नागरिकों के लिए अधिक सुविधा संपन्न , सुरक्षित और हाईटेक बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिस देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी मिशन में सूचीबद्ध किया गया था इस साल वो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड स्मार्ट सिटीज इंडिया अवाड्र्स-2022 की सेफ सिटी श्रेणी में अवार्ड भी जीत चुका है। आज उत्तराखंड की धामी सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तेज़ी से विकास की तरफ बढ़ रहा है।

उत्तराखंड सरकार ही नहीं केंद्र की मोदी सरकार का मेगा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी , ऐसे में डबल इंजन की सरकार में तेज़ी से हो रहा है स्मार्ट सिटी बनाने का निर्माण कार्य ... तो आइये आपको रूबरू कराते हैं देहरादून स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों और कुछ ऐसे फैक्ट्स से जिसको जानने की जिज्ञासा हर दूनवासी के मन में ज़रूर होगी।

आपको यहाँ पहले बता दें कि चरण 4 में देहरादून को स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था, और भारत सरकार द्वारा चुने गए 100 स्मार्ट शहरों में से एक था। 2017 में शहर को सूची में शामिल किया गया था, और स्मार्ट सिटी मिशन का स्थापना दिवस 25 जून 2019 को हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक साहसिक और नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार करना है। हालांकि, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य देहरादून के नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचा, एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, स्मार्ट समाधान अनुप्रयोग और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है।

आपको बताते हैं देहरादून स्मार्ट सिटी का क्या है उद्देश्य –

परियोजना का उद्देश्य शहर के लिए बुनियादी ढांचागत विकास प्रदान करना है

नागरिकों के लिए कर भुगतान, ई-गवर्नेंस आदि जैसे 'स्मार्ट' एप्लिकेशन समाधान प्रदान करें

राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

लोगों के लिए जीवन की एक सुरक्षित और सभ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना। इसे सुनिश्चित करने के लिए, अमृत, हृदय, स्वच्छ भारत, प्रधान मंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (शहरी) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसे विभिन्न अन्य प्रमुख मिशन भी योगदान करते हैं।

शहर के सतत विकास पर ध्यान दें। स्मार्ट सिटी मिशन देहरादून में 60 में से
द स
वार्ड शामिल हैं।

देहरादून स्मार्ट सिटी की कार्यान्वयन एजेंसी –

परियोजना को लागू करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल किया गया है। देहरादून के संवेदनशील और बिहार सक्रीय आईएएस अधिकारी डॉ आर राजेश कुमार एसपीवी के सीईओ और निदेशक हैं। जिनके अनुभव और सक्रीय कार्यशैली से आज देहरादून स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत चल रही अहम परियोजनाओं पर एक नज़र –

स्मार्ट शौचालयः इस परियोजना के तहत, डीएससीएल का लक्ष्य तीन परिसरों - महिलाओं और विकलांगों के साथ सात नए शौचालयों का निर्माण करना है। इन स्मार्ट शौचालयों का कुल क्षेत्रफल 665 वर्ग फुट होगा जिसमें सफाई और भुगतान संग्रह के लिए स्वचालित सुविधाएँ होंगी। साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए एक चाइल्ड केयर रूम बनाया जाएगा।

स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट्सः घर की बिजली और टेलीफोन केबल के लिए स्मार्ट सड़कों के किनारे मल्टी यूटिलिटी डक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसी भी मरम्मत कार्य के लिए बार-बार होने वाली खुदाई को कम करना है। हवाओं और तूफान से होने वाले नुकसान के कारण बार-बार रुकावट से बचने के लिए सभी बिजली के तार भी भूमिगत हो जाएंगे।

जल आपूर्ति वृद्धिः जल वितरण नेटवर्क के पुनर्गठन के लिए प्रस्तावित है, जो लगभग।36 कि.मी. नेहरू कॉलोनी में तीन नलकूप बदले जाएंगे, जो परेड ग्राउंड, दिलाराम चौक पर ओवरहेड टैंकों को भरते हैं। साथ ही, पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए कुछ नए नलकूपों का निर्माण किया गया है। तहसील क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ओवरहेड टैंक का निर्माण किया जायेगा.

सीवेज लाइन परियोजना : क्षेत्र का पुनर्गठन या सीवरेज सिस्टम को बदलने

आम लोगों को स्मार्ट सिटी के किए जा रहे कार्यों से किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाइ जाए ताकि इन विकास कार्यों का लाभ जनता को मिल सके... स्मार्ट सिटी के सभी काम तय समय पर पूरा करने के साथ ही उन्हें जनता के लिए व्यावहारिक बनाया जाए। पीपीपी मोड पर स्मार्ट पोल का काम इस साल दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं "

- प्रेमचंद अग्रवाल , कैबिनेट मंत्री

सबका भारत, निखरता भारत

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

प्रेमचंद अग्रवाल,
शहरी विकास एवं आवास मंत्री

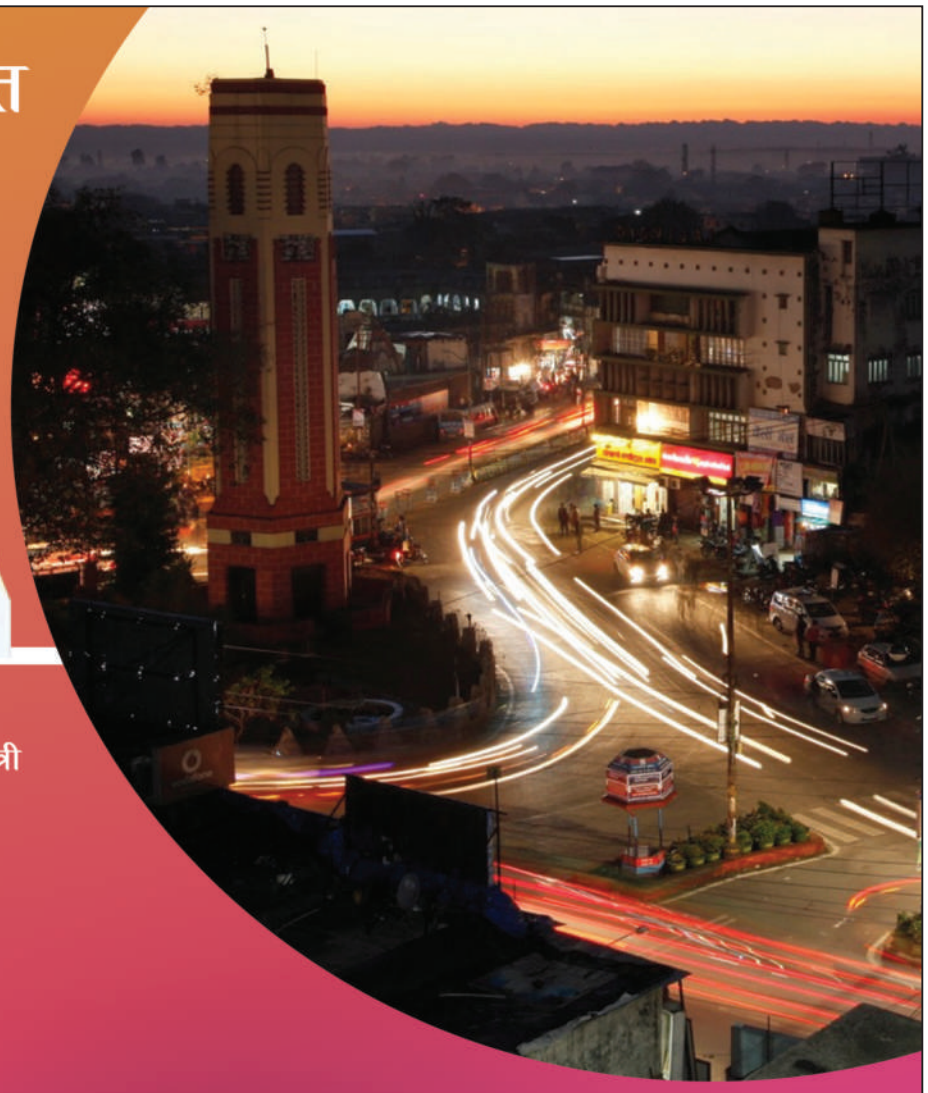

देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन ने पकड़ी रफ्तार, जल्द खत्म होगा आपका इंतजार

डॉ.आर. राजेश कुमार
सीईओ

206 ट्यूबवेल को अपग्रेड किया जा रहा है। नगर निगम को दो जटायु मशीन, दो स्वीपिंग मशीन, एक कॉम्पैक्टर, दो ड्रैन क्लीनिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही दो कॉम्पैक्टर, 20 हाकर टीपर, 20 ई–कार्टेज, की मशीन पांच दिए जाने के निर्देश दिए गए है।

अभी तक स्मार्ट स्कूल, वाटर एटीएम, ई कलक्ट्रेट, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम परियोजना पूर्ण हो चुकी है। डीआईसीसी के माध्यम से ५०० सीसीटीवी कैमरों, स्मार्ट टायलेट, दून लाईब्रेरी, स्मार्ट जल आपूर्ति संर्वद्धन का काम चल रहा है। घंटाघर से दिलाराम चौक, बहल चौक से आराघर, प्रिंस चौक से आराघर, घंटाघर से किसान नगर मार्ग पर स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित काम चल रहे है। यहां पर मल्टी यूटीलिटी डक, ड्रेनेज, सीवर और जल आपूर्ति के काम होने हैं।

सदैव दून
ICCC - Dehradun Smart City Ltd.

देहरादून स्मार्टसिटी लिमिटेड, देहरादून

का काम किया जाएगा। देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए सीवर नेटवर्क डिजाइन किया गया है, और कुछ नई सीवर लाइनें भी बनाई गई हैं।

स्मार्ट स्कूल: स्मार्ट स्कूल में आभासी कक्षाएं, डिजिटल सामग्री, स्कूल प्रबंधन प्रणाली, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक उपस्थिति शामिल हैं।

स्मार्ट वाटर सप्लाई स्काडा सिस्टमः सभी गैर-घरेलू कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। स्मार्ट मीटर में ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग की सुविधा होगी। रिमोट मीटर रीडिंग डिवाइस को फिट किया जाएगा और इसमें सॉफ्टवेयर आधारित बिल जनरेशन सिस्टम होगा। इसका उद्देश्य पानी की खपत को विनियमित करना, पानी के अनुशासन को लागू करना और आप जो उपभोग करते हैं उसके लिए भुगतान करना है।

दून लाइब्रेरी में स्मार्ट सॉल्यूशंस : अटैचिंग टैग, बुक ड्रॉप स्टेशन, स्मार्ट कार्ड की जानकारी, सेल्फ-चेक-इन / आउट सेंटर और एंटी-थेफ्ट अलार्म वाले आरएफआईडी गेट जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस लगाए जाएंगे।

शासकीय भवन में सौर ऊर्जा समाधान एवं वर्षा जल संचयन : हरित भवन को कुल 1100 किलोवाट भार दिया जाएगा। भवन के कुल कनेक्टेड लोड के 5% के साथ नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। कुल भार सौर पैनलों के माध्यम से उत्पन्न होगा, जो ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, जिसे छत पर स्थापित किया जाएगा।

वृक्षारोपणः शहर के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे।

क्रेच बिल्डिंग :

देहरादून सचिवालय परिसर के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक मॉडल क्रेच सुविधा का निर्माण किया जाएगा. डे-केयर सेंटर देहरादून सचिवालय के भीतर स्थित होगा। इसमें 3 से 10 साल के 30 बच्चे और छह शिशु रह सकते हैं।

देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति - 2022

फरवरी 2022 तक देहरादून स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति इस प्रकार हैः-

विवरण	परियोजनाओं	राशि खर्च
निविदा जारी	39	1537 करोड़ रुपये
काम पूरा हो गया है	18	503 करोड़ रुपये
कार्य आदेश चरण	39	1537 करोड़ रुपये

ये है स्मार्ट सिटी की प्रगति रिपोर्ट -

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ हुयी बैठक में जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पलटन बाजार में 49 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। दस इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है।

नगर निगम को सफाई के लिए मिलेंगी 42 मशीनें

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि शहरी विकास विभाग की ओर से सफाई की 42 मशीनें नगर निगम को उपलब्ध कराई जाएंगी। 206 ट्यूबवेल को अपग्रेड किया जा रहा है। नगर निगम को दो जटायु मशीन, दो स्वीपिंग मशीन, एक कॉम्पैक्टर, दो ड्रैन क्लीनिंग मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही दो कॉम्पैक्टर, 20 हाकर टीपर, 20 ई-कार्टेज, की मशीन पांच दिए जाने के निर्देश दिए गए है ।अभी तक स्मार्ट स्कूल, वाटर एटीएम, ई कलक्ट्रेट, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम परियोजना पूर्ण हो चुकी है। डीआईसीसी के माध्यम से 500 सीसीटीवी कैमरों, स्मार्ट टायलेट, दून लाईब्रेरी, स्मार्ट जल आपूर्ति संवर्द्धन का काम चल रहा है। घंटाघर से दि ला रा म चौ क , चौ क से आराघर, प्रिंस चौक से आराघर, घंटाघर से किसान नगर मार्ग पर स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित काम चल रहे है। यहां पर मल्टी यूटीलिटी डक, ड्रेनेज, सीवर और जल आपूर्ति के काम होने हैं।

बहल

विकल्प रहित संकल्प

आवास, विकास, सरलता,
संतुष्टि और प्रयास

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

हरिद्वार रुड़की
विकास प्राधिकरण

प्रेमचंद अग्रवाल,
शहरी विकास एवं
आवास मंत्री

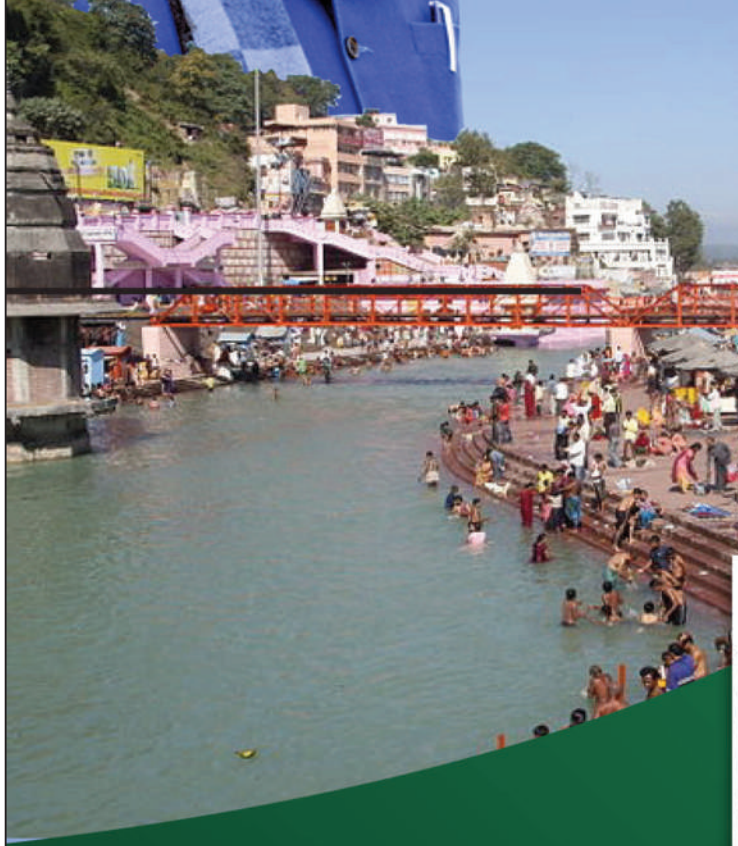

विनय शंकर पांडे (आईएएस)
उपाध्यक्ष : हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सौरभ बहुगुणा
पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड

➤ **(१) पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम :** प्रदेश के 1600 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र द्वारा ग्राम स्तर पर पशु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी।

➤ **(२) लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान :** राष्ट्र की प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य प्रयोगशाला उत्तराखंड में स्थापित है जिसके द्वारा वर्ष में 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादित की जा रही है। इनके प्रयोग से 90 प्रतिशत बछिया उत्पन्न होती है।

➤ **(३) प्रशिक्षण :** मैत्री व उपसा कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान का 120 दिवसीय परीक्षण उपलब्ध कराया जाता है जो क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान कार्य स्वरोजगा. री के रूप में संपादित करते हैं। इस प्रकार लगभग 716 स्वरोजगारियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं जिन्हें इस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

➤ **(४) भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम :** पशुओं की अनुवांशिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु इस तकनीक का प्रयोग पशु परिजन फार्म कालसी व क्षेत्रीय पशुपालकों के द्वारा पर किया जा रहा है जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है और कृषकों की आजीविका में सुधार हो रहा है।

➤ **(५) पशुधन बीमा योजना :** इस योजना अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक के पांच पशुओं का बीमा प्रीमियम पर 50 से 80 प्रतिशत अनुदान पर किया जा रहा है जिससे सामाजिक कल्याण वह कृषकों को पशु मृत्यु पर तत्काल क्षतिपूर्ति प्राप्त हो रही है।

➤ **(६) चारा विकास कार्यक्रम :** उत्तराखंड में लगभग 40 प्रतिशत चारे की कमी है जिससे दूर करने हेतु कंपैक्ट फीड ब्लाक तैयार कर विकासखंड स्तरीय चारा बैंकों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में यातायात अनुदान सहित आपूर्ति की जा रही है।

➤ **(७) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम :** राज्य में प्रत्येक जनपद में सफल कृत्रिम गर्भाधान का लाभ पशुपालकों को निशुल्क प्रदान किया जा रहा है जिससे पशु नस्ल सुधार में आशातीत वृद्धि होगी।

➤ **(८) पशु संजीवनी योजना :** इस योजना में पशुओं को विशिष्ट पहचान दिलाये जाने हेतु 12 डिजिट का ईयर टैग लगाकर इनाफ पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है तथा कृत्रिम गर्भाधान टीकाकरण बीमा इत्यादि की सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही है।

➤ **(९) एनडीएलएस :** पशुपालन डेयरी व मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा देश में प्रथम बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना जनपद देहरादून और हरिद्वार में क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में समस्त पशु चिकित्सालय का कंप्यूटरीकरण करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती की गई है।

उत्तराखंड सरकार के 100 दिवस पूर्ण होने पर पशुपालन विभाग की एक और उपलब्धि

अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला पर कुल 242625 अवर्गीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 137057 वीर्य स्ट्रा का विक्रय अन्य राज्यों को किया गया। इसी के साथ ही 1.15 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य का विक्रय उड़ीसा राज्य को रु. 822 लाख में किया गया

पशु प्रजनन फार्म कालसी में देश भर के 6 वैज्ञानिकों को ओबम पिंक अब तथा अंतरराष्ट्रीय (नेपाल) के 4 पशु चिकित्साविदों को प्रशिक्षण दिया गया

पशु प्रजनन फार्म कालसी में पशुपालकों के उन्नत पशुओं में आईवीएफ तकनीक द्वारा 41 सफल गर्भधारण, 100 भ्रूण का उत्पादन किया गया

एनडीआरआई करनाल के उच्च आनुवंशिक गुणों के चार साहिवाल सांडों का लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन किए जाने हेतु अनुबंध किया गया

राज्य के 95 विकासखंड स्तर पर गोवंश एवं महिषवंशीय पशुओं में बांझपन निवारण कैम्पों का आयोजन किया गया

हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस

देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022

देवभूमि में श्वेत क्रांति लाएगी आँचल में खुशहाली : सौरभ बहुगुणा, दुग्ध एवं पशुपालन मंत्री

आंचल ब्रांड राज्य का अपना ब्रांड है और लोगों से इसका रिश्ता पुराना है। इसी कड़ी में हम और नई संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। जिसके तहत अब जल्द ही लालकुआं में एक लाख लीटर दैनिक क्षमता का अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित किया जायेगा

- सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री

मंत्री सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में आँचल की ऊँची उड़ान - आइस्क्रीम हुई सुपरहिट, अब कैफे का एलान

उत्तराखंड में बीते 100 दिनों की उपलब्धियों की बात करें तो श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने करिश्माई परिणाम दिए हैं। आँचल डेयरी को आधुनिकता के साथ पर्यटन सीजन में बड़े पैमाने पर लांच करने के लिए पहले सौ दिन में ही आँचल आइस्क्रीम की सुपरहिट लांचिंग ने मंत्री बहुगुणा की दूरगामी सोच का नमूना पेश कर दिया है। अंचल आइस्क्रीम ने शुरूआती महीने में ही लाखों का मुनाफ़ा महकमे को दिया है। इस कामयाबी से उत्साहित दुग्ध और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने घोषणा की है क़ी जल्द ही देश दुनिया से देवभूमि आ रहे पर्यटकों को आँचल कैफे की सौगात देने जा रहे हैं।

पहाड़ से लेकर मैदान तक महिलाओं और युवाओं को रोज़गार से जोड़ने में आज आँचल डेयरी ही नहीं समूचा दुग्ध एवं पशुपालन विभाग एक बड़ी भूमिका निभाता नज़र आ रहा है। ये मुमकिन हो रहा है धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन और दूरदर्शी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विजन से

प्रदेश में आज अनेक ऐसी योजनाएं चल रही है जिसका लाभ दुग्ध उत्पादकों को स्वरोजगार के रूप में मिल रहा है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पशुपालकों और कृषकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि दुग्ध विकास विभाग श्वेत क्रांति के क्षेत्र में सतत प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों को इसका लाभ उठाना चाहिए। देश में आइसक्रीम के अन्य ब्रांडों से उच्च कोटि की आइसक्रीम आंचल की ओर से बनाई जा रही है। सौ दिनों की उपलब्धियों पर बात करते हुए पशुपालन, दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय महिला समूहों एवं युवाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। चार धाम यात्रा में देश भर से लोग आ रहे हैं ऐसे में आँचल की ब्रांडिंग एक बड़ा और सफल प्रयास है जिसमें अभूतपूर्व कामयाबी मिलने से विभाग के अधिकारी और सरकार उत्साहित है।

मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में मत्स्य पालन की अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं को मत्स्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए, जिससे पलायन और बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सके। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में जल्द ही पीपीपी मोड पर आंचल कैफे लांच किए जाएंगे, जिससे कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सितम्बर से विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भी विभाग आंचल दूध, कुल्फी तथा आइसक्रीम आदि उत्पादों की बिक्री हेतु आंचल क्योस खोलने की तैयारी की जा रही है।

आँचल डेयरी को प्रदेश का बड़ा ब्रांड बनाने के लिए लगातार अनेकों नई प्रोजेक्ट लांच करते हुए अब मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में 2900 महिला समूह हैं जो कि कोऑपरेटिव में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन से जोड़ने का काम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा।

AANCHAL ICE CREAM

AANCHAL

With Real Milk inside...

Pure Milk Mein Bani Pure Ice Cream

FAMILY PACK - 700 ML

VANILLA
120/-

CHOCOLATE CHIP
130/-

KESAR PISTA
150/-

BUTTERSCOTCH
125/-

TUTTI FRUTTI
135/-

FRESH STRAWBERRY
120/-

Ice Candy
50 ml

ORANGE
10/-

DOLLY
50 ml

MANGO
20/-

CONICAL KULFI
50 ml

PUNJABI
25/-

CONICAL KULFI
50 ml

RABRI
20/-

CHOCOBAR
50 ml

NUTTY CHOCOBAR
20/-

CUP - 90 ML

CHOCOLATE
25/-

BUTTERSCOTCH
25/-

VANILLA
20/-

STRAWBERRY
20/-

CONE CRUNCHOZ - 110 ML

CHOCOLATE
35/-

BUTTERSCOTCH
30/-

Family Pack - 5000 ML

VANILLA
700/-

FRESH STRAWBERRY
700/-

BUTTERSCOTCH
800/-

For Business Enquiry
9368896247, 9193000977

Uttarakhand Cooperative Dairy Federation Limited, Mangal Parao, Haldwani-263139
ucdfltd@gmail.com Customer Care Number - 05946-255358

दैनिक न्यूज़ वायरस

विकास के 100 दिन

भारतीय राजनीति के दिग्गज बहुगुणा खानदान से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा कैबिनेट मंत्री और सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा प्रदेशगन्ना, पशुपालन मंत्री और प्रोटोकॉल मंत्री है। सहज स्वभाव , हल्की मुस्कान और दरख्वास्त पर तुरंत कार्यवाही करते हुए फरियादी को संतुष्टि देकर सौरभ बहुगुणा कहते हैं किहम आपसे अलग नहीं हैं। हम आप ही में से एक हैं। हमें आपने चुनकर भेजा है। अपने सौ दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा कहते हैं कि गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान , आँचल डेयरी की ब्रांडिंग और आइसक्रीम के साथ फ्लेवर्ड मिल्क प्रोडक्ट , दुग्ध समूहों के ज़रिये महिलाओं को रोज़गार से जोड़ना औरचीनी मिलों की समस्याओंको दूर कर उनके आधुनिकीकरण करने के दिशा में किये गए प्रयास बड़ी कामयाबी है।

युवा मंत्री सौरभ न्यूज़ वायरस से सौ दिन की उपलब्धियों पर बात की तो उन्होंने कहा किमुझे जब मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने खुद से कुछ वादे किए थे। जिनमें से पहला यह था कि मैं दफ्तर से ज्यादा जमीन पर रहकर काम करूंगा। यह मेरा सौभाग्य था कि पशुओं का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे मिली। केदारनाथ यात्रा में पशु क्रूरता, उनकी सेहत व अन्य कठिनाइयों आदि के जो मामले आ रहे थे, उनमें जो कमी एवं सुधार आ रहा है, उसकी रिपोर्ट आपके सामने है।

एक नज़र डालते हैंमंत्री सौरभ बहुगुणा के100 दिन के विभागीय उपलब्धियों पर –

❖ हली बार सरकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान कर दी बड़ी राहत

❖ प्रदेश की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण करने की योजना तैयार

❖ पहाड़ से पलायन को रोकने के लिए विभागों को योजना बनाने के दिए निर्देश

❖ मत्स्य पालन, दुग्ध विकास व पशुपालन विभाग की योजनाओं में तेज़ी लाने के निर्देश

❖ आम लोगों की पहुँच को आसान बनाने के लिए दफ्तर और आवास में की व्यवस्था

❖ सितारगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत बनने जा रहे 1168 ई डब्ल्यू एस आवासीय भवन निर्माण में तेज़ी आई

❖ उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद योजना का लाभ पात्र लोगों को देने के लिए जांच कर आवंटन के निर्देश

❖ प्रदेश के हर कोने में दौरे कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने पर ज़ोर

❖ राज्य भेड़ बकरी अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन व कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशाला, पशुलोक की सौगात दी

❖ देहरादून ओर नैनीताल में आँचल आइसक्रीम की शुरुआत एक बड़ी सफलता

❖ लांचिंग के साथ ही 15 लाख की आइस्क्रीम की बिक्री कर आँचल ब्रांड को बनाया लोकप्रिय

❖ आँचल कैफे योजना से युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की तैयारी

❖ चार धाम यात्रा मार्गों पर सितंबर से होगी आँचल प्रोडक्ट्स की बिक्री

❖ दुग्ध उद्योग से पहाड़ की 50 हज़ार महिलाओं को जोड़ा गया

❖ उधमसिंह नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2900 महिला समूह को जोड़ने की योजना

❖ मुर्गी , बकरी , गाय पालन के लिए सब्सिडी देकर युवाओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना

❖ उधमसिंह नगर में बंगाली समुदाय के उत्थान की योजना बनाने का निर्देश

❖ पशुपालन विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए निर्देश

❖ बायफ संस्था के सहयोग से कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने के निर्देश

❖ कर्मचारियों और अधिकारियों को जनता के हितों के लिए बिना दबाव कार्य करने के लिए निर्देश

❖ गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव में घोड़े एवं खच्चरों के आराम करने हेतु टिन शेड निर्माण का आदेश

❖ Semi-stall feeding बकरी पालन मॉडल को लेकर उन्हें अहम दिशा निर्देश

❖ पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बकरी पालन रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश

❖ कौशल विकास, गन्ना विकास, पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग में तेज़ हुई फाइलों की रफ़्तार

❖ लालकुआं में एक लाख लीटर दैनिक क्षमता का अत्याधुनिक डेयरी प्लांट स्थापित करने कक फैसला

❖ नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लाल कुआं को भविष्य की रणनीति तैयार करने का दिया निर्देश

❖ तीनमोबाइल वैनकौशल रथ के ज़रिये प्रदेश के युवाओं को जागरूक करने का अभियान

❖ केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग परघोड़े-खच्चरों की सेहत के लिए उचित निर्देश

❖ सितारगंज गन्ना सोसाइटी के कर्मचारियों के 16 महीनों से लंबित 57 लाख रुपए की राशि के चेक वितरित

❖ चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिए जाने के लिएप्रस्ताव तैयार करने के निर्देश

v कृत्रिम गर्भाधान के लिए जाने वाले कार्मिकों को मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए देने का फैसला

हिंदी दैनिक न्यूज़ वायरस

देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022

विकल्प रहित संकल्प के 100 दिनों की उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा हासिल बड़ी उपलब्धियों पर एक नज़र

(1) पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रदेश के 1600 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र द्वारा ग्राम स्तर पर पशु कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिससे दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी।

(2) लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान : राष्ट्र की प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य प्रयोगशाला उत्तराखंड में स्थापित है जिसके द्वारा वर्ष में 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादित की जा रही है। इनके प्रयोग से 90 प्रतिशत बछिया उत्पन्न होती है।

(3) प्रशिक्षण : मैत्री व उपसा कार्यकर्ताओं को कृत्रिम गर्भाधान का 120 दिवसीय परीक्षण उपलब्ध कराया जाता है जो क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान कार्य स्वरोजगारी के रूप में संपादित करते हैं। इस प्रकार लगभग 716 स्वरोजगारियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं जिन्हें इस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।

(4) भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम : पशुओं की अनुवांशिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु इस तकनीक का प्रयोग पशु परिजन फार्म कालसी व क्षेत्रीय पशुपालकों के द्वारा पर किया जा रहा है जिससे दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है और कृषकों की आजीविका में सुधार हो रहा है।

(5) पशुधन बीमा योजना : इस योजना अंतर्गत प्रत्येक पशुपालक के पांच पशुओं का बीमा प्रीमियम पर 50 से 80 प्रतिशत अनुदान पर किया जा रहा है जिससे सामाजिक कल्याण वह कृषकों को पशु मृत्यु पर तत्काल क्षतिपूर्ति प्राप्त हो रही है।

(6) चारा विकास कार्यक्रम : उत्तराखंड में लगभग 40 प्रतिशत चारे की कमी है जिससे दूर करने हेतु कंपैक्ट फीड ब्लाक तैयार कर विकासखंड स्तरीय चारा बैंकों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में यातायात अनुदान सहित आपूर्ति की जा रही है।

(7) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम : राज्य में प्रत्येक जनपद में सफल कृत्रिम गर्भाधान का लाभ पशुपालकों को निशुल्क प्रदान किया जा रहा है जिससे पशु नस्ल सुधार में आशातीत वृद्धि होगी।

(8) पशु संजीवनी योजना : इस योजना में पशुओं को विशिष्ट पहचान दिलाये जाने हेतु 12 डिजिट का ईयर टैग लगाकर इनाफ पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है तथा कृत्रिम गर्भाधान टीकाकरण बीमा इत्यादि की सुविधा पशुपालकों को उपलब्ध कराई जा रही है।

(9) एनडीएलएस: पशुपालन डेयरी व मत्स्य विभाग भारत सरकार द्वारा देश में प्रथम बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप मं योजना जनपद देहरादून और हरिद्वार में क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में समस्त पशु चिकित्सालय का कंप्यूटरीकरण करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती की गई है।

उत्तराखंड सरकार के 100 दिवस पूर्ण होने पर पशुपालन विभाग की एक और उपलब्धि पर डालते हैं नजर

- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला पर कुल 242625 अवर्गीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 137057 वीर्य स्ट्रा का विक्रय अन्य राज्यों को किया गया। इसी के साथ ही 1.15 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य का विक्रय उड़ीसा राज्य को रु.822 लाख में किया गया
- पशु प्रजनन फार्म कालसी में देश भर के 6 वैज्ञानिकों को ओबम पिंक अब तथा अंतरराष्ट्रीय (नेपाल) के 4 पशु चिकित्साविदों को प्रशिक्षण दिया गया
- पशु प्रजनन फार्म कालसी में पशुपालकों के उन्नत पशुओं में आईवीएफ तकनीक द्वारा 41 सफल गर्भधारण , 100 भ्रूण का उत्पादन किया गया
- एनडीआरआई करनाल के उच्च आनुवंशिक गुणों के चार साहिवाल सांडों का लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन किए जाने हेतु अनुबंध किया गया
- राज्य के 95 विकासखंड स्तर पर गोवंश एवं महिषवंशीय पशुओं में बांझपन निवारण कैम्पों का आयोजन किया गया

दैनिक न्यूज़ वायरस विकास के 100 दिन

बागेश्वर के चार बार के विधायक व वर्तमान में समाज कल्याण एवं परिवहन विभाग का दायित्व संभाले चंदन राम दास मूल रूप से द्वाराहाट ब्लॉक के कांडे गांव के निवासी हैं। हालांकि बजट सत्र के बीच में ही मंत्री दास की तबियत खराब हो गयी थी जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच धामी सरकार अपने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रख रही है। परिवहन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री चंदन राम दास का कहना है कि गरीबों के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। समाज के अंतिम छोर के गरीब व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना धामी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जिस जनता ने चुनकर उन्हें यहां तक पहुंचाया है, वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे , साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश का विकास करेंगे

- चंदन राम दास , कैबिनेट मंत्री

- अधिकारियों को सौ दिन के भीतर सभी रोडमैप तैयार करने का निर्देश
- रोडवेज की कोई भी डिपो मर्ज न करने और भविष्य में और डिपो खोलने के निर्देश
- अल्मोड़ा में आईएसबीटी बनाने के लिए तेज़ हुई कार्यवाही
- सीएनजी बसों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की योजना पर ज़ोर
- रोडवेज की बसों में सुधार कर यात्रियों को अच्छी सुविधा देने के निर्देश
- रोडवेज के चालकों को नियमित तनख्वाह दिए जाने के निर्देश
- बागेश्वर में रोडवेज डिपो खोलने की दिशा में पहल
- गंगोलीहाट-पिथौरागढ़ रूट पर जल्द होगा रोडवेज बस का संचालन
- समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर सख्त निर्देश
- बागनाथ धाम को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने का फैसला
- केंद्र सरकार से 52 करोड़ रुपये स्वीकृत कराने में मिली सफलता
- रोडवेज और समाज कल्याण विभाग की सुस्त फाइलों को तेज़ी से निपटने पर दिया ज़ोर
- आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान को मिली कामयाबी
- सभी पेंशन व मानदेय में बढ़ोतरी करने का कल्याणकारी फैसला
- चारधाम यात्रा में 16 हजार वाहन , 50 केएमओयू व 150 परिवहन विभाग की बसें संचालित करने का फैसला
- जागेश्वर, बागेश्वर व बैजनाथ को पांचवें धाम के रूप में विकसित करने की योजना
- देवभूमि में धूम्रपान निषेध करने / रोकने के लिए विशेष अभियान के दिए निर्देश
- राज्य के सभी 425 मदरसों की जांच के आदेश दिए
- मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश
- मदरसों पर शिक्षा विभाग के नियम लागू करने के दिए निर्देश
- फारेस्ट फायर रोकने को बागेश्वर के जौलकांडे में बना पहला मॉडल क्रू स्टेशन

दैनिक न्यूज़ वायरस

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत

वर्तमान सरकार के
100 दिन का कार्यकाल
पूर्ण होने की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

चंदन राम दास
मंत्री, समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, छात्र कल्याण परिवहन, लघु सूक्ष्म, मध्यम उद्यम व खादी, ग्रामोद्योग

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक-2022

1. राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं उन्हें राज्य विधियों के अधीन प्राप्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों/ अनुमोदनों/ अनुज्ञापनों/ अनुज्ञप्तियों/ अनुमतियों में विथिलीकरण/छूट प्रदान किये जाने के लिए उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक-2022 बजट सत्र-2022 में पारित किया गया।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त राज्य विधियों के अधीन स्वीकृतियां/अनापत्तियां प्राप्त किये जाने हेतु तीन वर्ष की समयावधि प्रदान की गई है। इस अवधि में इन उद्यमों को राज्य विधियों के अधीन निरीक्षणों से छूट प्रदान की जायेगी।
- मध्यम उद्यम राज्य विधियों के अधीन तीन वर्ष अथवा व्यवसायिक उत्पादन की तिथि, जो भी पहले हो तक स्वीकृतियां/अनापत्तियां प्राप्त कर सकेगें।
- इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने वाले चार राज्यों में उत्तराखण्ड सम्मिलित है।

स्वरोजगार योजनाओं में ब्लॉक स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम/ कैम्पों का आयोजन एवं 100 प्रतिशत आवेदनों को बैंकों को प्रेषण

- विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत योजना का प्रचार-प्रसार करते हुये ब्लॉक स्तर तक 200 से अधिक कैम्पों का आयोजन किया गया है। इन आयोजनों में युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया गया। कैम्पों में ही आवेदन पत्र प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गई।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लक्ष्य से डेढ़ गुना कुल 10048 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 28 जून, 2022 तक कुल 1297 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को वित्त पोषण हेतु अग्रसारित।

सिंगल विण्डो व्यवस्था के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं को पूर्णत: ऑनलाइन करना।

- व्यवस्था के अन्तर्गत 177 सेवायें अधिसूचित हैं।
- 160 सेवाओं को ऑनलाईन किया जा चुका है।
- शेष 17 सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

भौगोलिक संकेतांक प्रमाणीकरण (Geographical Indications Certification)

- राज्य के 5 हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों भोटिया दन,ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखण्ड ताम्र उत्पाद एवं थुलमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जी0आई0) प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में प्रथम बार 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जी0आई0 प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2022 में निम्न 5 उत्पादों के जी0आई0 फाईल कर दिये गये हैं:-
- नेटल(बिच्छू घास), पिछौड़ा, नैनीताल की आर्टिस्टिक कैण्डल, जनपद चमोली से मुखौटा एवं रुद्रप्रयाग से मन्दिर प्रतिकृति।
- भौगोलिक संकेतांक(जी0आई0) प्राप्त होने से इन उत्पादों को राष्ट्रीय /अन्तराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने एवं उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता होगी।

कम्पलाइंस बर्डन रिडक्शन

- कम्पलाइंस बर्डन रिडक्शन के अन्तर्गत 768 कम्पलाइंस चिन्हित की गई हैं।
- पोर्टल पर 638 कम्पलाइंस अपलोड की गई हैं।
- 231 कम्पलाइंस को रिड्यूस किया जा चुका है।

ISBT – Housing Scheme

Indira Market

City Park

Dhaulas Housing Scheme

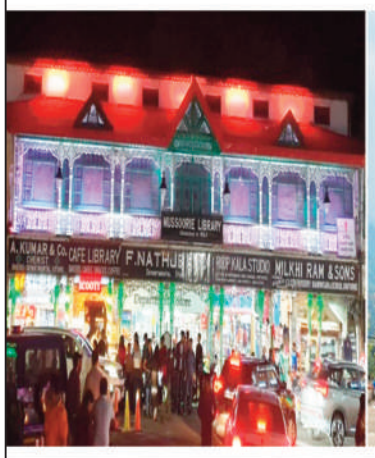

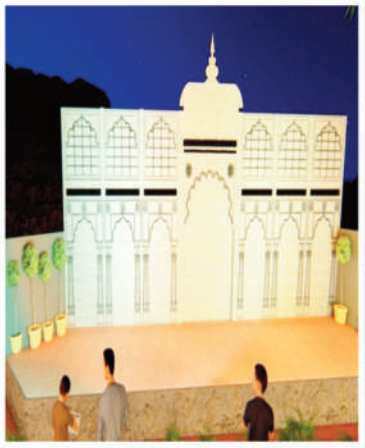

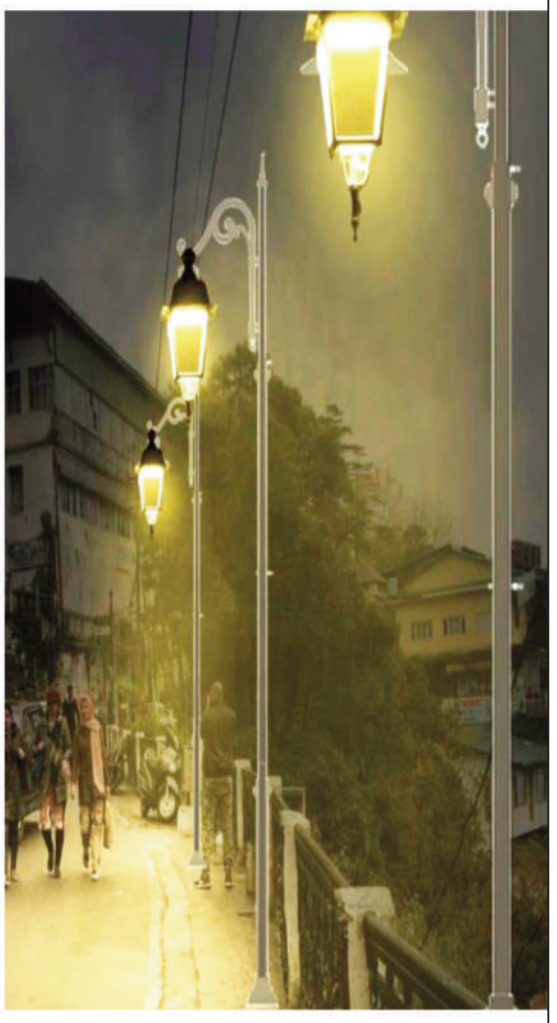

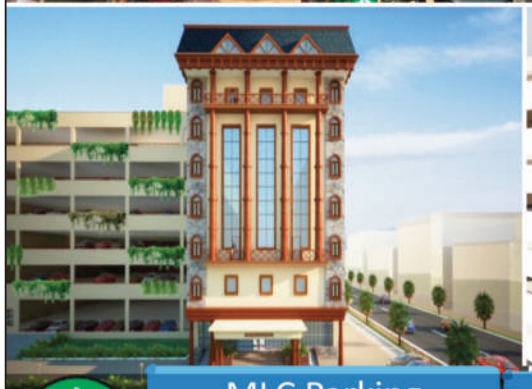

MLC Parking

Zero Point Multi Level Car Parking

Mussoorie – Facade

Mussoorie Dehradun Development Authority ★ Dehradun ★

MDDA- Transformation Through Innovation, Development and Adaptation

उत्तराखण्ड शासन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

100 दिन
विकास के
समर्पण और प्रयास के

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि

गरीबों को तीन गैस सिलेण्डर मुफ्त

भारतमाला परियोजना में 500 कि.मी. सड़कों का हो रहा निर्माण

टिहरी क्षेत्र को ब्राण्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए ₹1,930 करोड़

समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

पर्वत माला परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में विभिन्न रोपवे का निर्माण

4 हजार से अधिक होम स्टे पंजीकृत, 12 हजार से अधिक लोगों को मिला रोजगार

वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह, अब पात्र पति व पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन

एक वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लिए ₹14,387 करोड़ की विकास योजनाएं स्वीकृत

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 9.30 लाख किसानों को ₹1,581 करोड़ का भुगतान

कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु मानस खण्ड मंदिर माला मिशन की कार्य योजना पर कार्य प्रारम्भ

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत 42.9 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा 4.76 लाख मरीजों का मुफ्त ईलाज

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान योजना के अन्तर्गत 1.21 लाख से अधिक किसानों को ₹800 करोड़ से अधिक का ऋण बिना ब्याज के

उत्तराखण्ड के वीरता पदक सैनिकों को अनुदान में भारी वृद्धि

परमवीर चक्र ₹50 लाख, **महावीर एवं कीर्ति चक्र** ₹35 लाख, **वीर एवं शौर्य चक्र** ₹25 लाख, **सेना गेलेन्ट्री मेडल** ₹15 लाख

विकल्प रहित संकल्प

हमारी सरकार के इस कार्यकाल के 100 दिन विकास, समर्पण और प्रयास के रहे हैं, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प को 2025 में जब उत्तराखण्ड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहा होगा तब तक पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | DIPR_UK | UttarakhandDIPR | UttarakhandDIPR

दैनिक न्यूज़ वायरस

विकास के 100 दिन

जनता से जुड़ाव , मौके पर पहुंचकर अफसरों को निर्देश देना , बारिश होया आपदा धामी सरकार के ये मंत्री प्रभावित इलाके पर पहुँचते ज़रूर हैं। यूँ तो दुनियाभर में पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम मशहूर है लेकिन इसको संजोने संवारने और सुविधा संपन्न बनानेविधायक और उत्तराखंड सरकार में कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का योगदान ही है जो उन्हें हर बार प्रचंड बहुमत से जीतकर विधान सभा भेजता है। अपनी मंत्रालयों की बैठक हो , प्रदेश भर का दौरा हो या आदेश को पालन करवाने की कला हो , मंत्री गणेश जोशी बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों और विभागों तक मंत्री जोशी की सक्रियता नज़र आती है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के बीते सौ दिनों में मंत्री गणेश जोशी लगातार बैठकों और आदेशों के बीच खासे सक्रिय दिखाई दिए हैं। आइये उनके विभागीय आदेशों और उपलब्धियों पर डालते हैं एक नज़र

सगंध पौधा केन्द्र, जड़ी बूटी शोध संस्थान, भेषज विकास इकाई, उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद, रेशम विकास, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार, बीज प्रमाणीकरण, जैविक उत्पाद परिषद एवं उत्तराखण्ड तराई तथा बीज विकास निगम से संबंधित विकास योजनाओं कोमिली रफ़्तार

❖ प्रदेश के एरोमेटिक एवं जड़ी-बूटी उत्पादों को विदेशी बाजार तक पहुंचाने की योजना तैयार

❖ विभागों को आपसी समन्वय व तालमेल बढाकर कार्य करने के निर्देश

❖ इकाइयों के एकीकरण का अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश

❖ हर खेत को पानी मिले योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर बागवानी किसानों को 70 प्रतिशत और सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी वहीं फाउंटेन प्लांट लगाने पर छोटे और सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत और अन्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के निर्देश

❖ किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाओं को लागू करने पर ज़ोर

❖ राज्य के सभी 13 जनपदों केविजन डॉक्यूमेंट हेतु सुझाव साझा करने का निर्देश

❖ औद्यानिकी और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार सृजन कर पलायन को रोकने की योजना पर ज़ोर

❖ विभागों में समयबद्ध लक्ष्य तय कर जनता को रिजल्ट देने की कार्यशैली विकसित करने पर ज़ोर

❖ महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर -

❖ राज्य में ''एनआरएलएम'' के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों विशेष तौर पर महिला समूहों की आय को बढ़ाने पर ज़ोर

❖ एसएचजी द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को एक अम्ब्रेला ब्राण्ड के अंतर्गत ला कर उसे राज्य के ब्राण्ड के तौर पर मार्केट देने पर ज़ोर

❖ अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा सहायतित 771 करोड़ की रूरल इंटप्राइज एक्सलरेशन प्रोग्राम योजना लांच

❖ ग्राम्य विकास विभागांतर्गत विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को बांटे गए योजना से संबंधित चेक

❖ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)'' के तहत राज्य में तैयार 5000 आवासों का लाभार्थियों को आवंटन

❖ दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना (ग्रामीण)'' के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त 50 लाभार्थियों को दिया नियुक्ति पत्र

❖ महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्टेट लेवल आउटलेट का उद्घाटन

❖ महिला स्वयं सहायता समूहों को आय संवर्धन तथा व्यवसाय के लिए रिवाल्विंग फण्ड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड भी वितरित

❖ विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ करवेंजेस के माध्यम से लाभार्थियों को देने के निर्देश

❖ उद्यान विभाग, भेषज, कृषि विभाग मशरूम उत्पादन तथा ग्राम्य विकास विभागांतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का कनवर्जेंस करने के निर्देश

❖ पीएमजीएसवाईसड़कोंके गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों पर सख्ती के निर्देश

❖ योजनाओं के प्रचार प्रसार पर फोकस -

❖ योजनाओं को सरल और सहज भाषा में आम नागरिकों तक पहुंचाए जाने की योजना पर फोकस

❖ सोशल मीडिया का अधिकतम प्रयोग , ग्राम्य विकास की सभी योजनाओंकी जानकारी देने वाला न्यूज लेटर निकालने के निर्देश

❖ उत्तराखंड उदीयमान छात्र योजना में 100 विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए का अनुदान देने की योजना

❖ सैन्यधाम निर्माण कार्यों में आई तेज़ीविभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश

❖ टनकपुर व गोपेश्वर में विश्रामगृहों के शिलान्यास की तैयारियों पर कार्य हुआ तेज़

❖ कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र के लिए विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए।

❖ अखरोट , कीवी , सेब के उत्पादन को आगामी 5 वर्षों में कई गुना तक बढ़ाने की योजना पर कार्य

❖ औषधीय तथा सगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने तथा शोध कार्यों को सीधे किसानों से जोड़े जाने के निर्देश

❖ विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को राज सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित करने के निर्देश

❖ विभागों को आगामी 5 वर्षों के लिए एक्शन एवं विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश

❖ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15000 पक्के आवास आवंटित करने की योजना पर काम शुरूमसूरी विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम 75 छोटी झीलों अथवा तालाबों का निर्माण कराने के निर्देश

❖ काठगोदामउद्यान विभाग को छोटे किसानों को समय पर अदरक, हल्दी, लहसुन,मटर आदि के बीजों का वितरण करने के निर्देश

❖ सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारीयों को सैनिक विश्राम गृहों को हाईटेक करने का निर्देश

❖ ग्राम्य विकास एवं पीएमजीएसवाई की अधिग्रहित ज़मीनों का समय पर मुआवजा देने के निर्देश

❖ राज्य के 36 सैनिक विश्राम गृहों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माणके कार्यों में आई तेज़ी

❖ टनकपुर, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश में आलीशान सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण करने के निर्देश

❖ पीएमजीएसवाईमें लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करते हुए इन कार्यों को रिटेंडर करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश

❖ औद्योगिक ''हैम्प'' एवं चिकित्सकीय ''कैनेबिस'' नियमावली ड्राफ्ट करने के निर्देश

❖ किसानों को सम्मानित कर सगंध खेती को प्रोत्साहित करने केनिर्देश

❖ पिथौरागढ़ मेंसैनिक विश्राम ग्रह को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए।

❖ टीडीसी को घाटे से उबारने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश

❖ कृषकों तक मण्डी परिषद की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश

❖ गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को जैविक खेती पर अधिक से अधिक बल देने के निर्देश

❖ यूनिवर्सिटी द्वारा किये जाने वाले शोध कार्यों का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन करने के निर्देश

❖ गलोगी के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए डी.पी.आर. तैयारकर जल्द ही कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश

❖ किसानों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने हेतु जल्द ही एक किसान हेल्पलाइन शुरू करने के निर्देश

❖ अन्य पड़ोसी राज्यों का अध्ययन कर सब्सीडी राशि को पुर्ननिर्धारित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश

❖ रेशम कृषकों को उचित सहायता प्रदान कर उनके हितों के लिए कार्य करने के निर्देश

ऊधम सिंह नगर
महिला सशक्तिकरण
की ओर अग्रसर
विकल्प
रहित
संकल्प
पुष्कर सिंह धामी
(मुख्यमंत्री, उत्तराखंड)
जनपद - ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
युगल किशोर पंत
जिलाधिकारी
जनपद ऊधम सिंह नगर

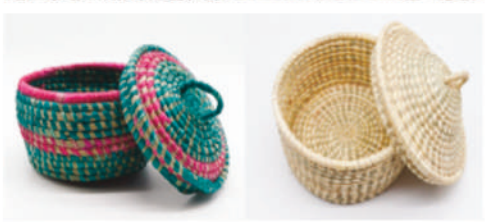

दैनिक न्यूज़ वायरस विकास के 100 दिन

महिला एवं बाल विकास, खेल एवं खाद्य मंत्री रेखा आर्य

उत्तराखंड की सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में एक और मंत्री अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। कभी अपने तेवर तो कभी अपने ज़ेवर की वजह से अख़बारों की सुर्खियां बनने वाली महिला एवं बाल विकास , खेल एवं खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खुद को प्रदेश के बच्चों की बुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामा बताकर अपनी वाक्पटुता का भी परिचय दिया है। प्रदेश की धामी सरकार के बीते सौ दिनों के सफल कार्यकाल पर नज़र डाले तो मंत्री आर्या के हिस्से भी लम्बी उपलब्धि आई है। महिलाओं के संघर्ष से जन्म लेने वाले प्रदेश में महिलाओं का कल्याण , उनका संरक्षण और बालिकाओं को सुरक्षा , शिक्षा देना मंत्री रेखा आर्या की प्राथमिकताओं में शामिल है। बीते दिनों गुजरात के केवड़िया में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ₹खेल एवं युवा मामलों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन₹ शामिल हुई मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की खेल नीति और खेल प्रतिभाओं को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं।

उत्तराखंड के एक साधारण घर की बेटी रेखा ने अपनी ज़िं द गी का हर पन्ना कड़ी मेहनत और संघर्ष से लिखा है। वो आज एक कामयाब लीडर ही नहीं लाखों महिलाओं के लिए मिसाल हैं , जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर के नवरत्नों में शामिल रेखा आर्या के कंधे पर बड़े विभागों का ज़िम्मा है।

बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि ये सौ दिन सफलता के सौ दिन हैं। 'इन सौ दिनों में हमने कई योजनाओं को विस्तार दिया है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि सत्ता में आते ही हम गरीब परिवारों को साल में तीन गैस सिलेंडर फ्री देंगे। वह स्कीम शुरू कर चुके हैं। हम नयी खेल नीति लाने जा रहे हैं , इसके अलावा और भी कई योजनाएं जल्द सामने आने वाली हैं।

ब्यूरोक्रेसी के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए अनुशासन और प्रोटोकॉल की मुखर हिमायती मंत्री रेखा कराया ने सौ दिनों में यूँ तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर अनेकों लोकहित और जनहित के फैसले किये हैं लेकिन हम आपको उनके द्वारा लिए गए कुछ ख़ास और बड़े फैसलों के बारे में यहाँ बता रहे हैं।

'अपात्र को ना, पात्र को हां'

उत्तराखंड में 'अपात्र को ना, पात्र को हां अभियान के तहत राशन कार्ड सरेंडर किए गए। योजना के तहत राज्य में 58,374 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए और अब पात्रों तक ये राशन पहुंचाने का काम राज्य सरकार कर रही है।

ग्रेन एटीएम वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड –

खाद्य मंत्री रेखा आर्या की योजना के मुताबिक जल्द ही विश्व खाद्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में एटीएम से लोगों को गेंहूं , दाल और चावल मिलने लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों को सहूलियत होगी बल्कि पारदर्शितालाभार्थियों तक सीधे अनाज पहुंचेगा

पहाड़ी क्षेत्रों के खाद्य विभाग से संचालित सस्ते गल्ले / राशन दुकानदारों को मिली राहत –

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 5 माह का राशन ए क साथ उठाए जाने को कहा जा रहा है । दुकानदारों के पास भंडारण की क्षमता ना होने के कारण राशन खराब होने की आशंका है, इस पर तत्काल रोक लगा दी जाए तथा पूर्व प्रचलित व्यवस्था को बहाल रखने का फैसला किया गया

राशन डीलरों को बेहतरीन लैपटॉप की सुविधा –

राशन डीलरों को दिए गए सरकारी लैपटॉपों की खराब वह घटिया किस्म के होने की शिकायतों की जांच करके इनके स्थान पर अच्छी कंपनी के लैपटॉप दिए जाने का फैसला भी एक बेहतरीन कदम साबित होने वाला बताया जा रहा है।

प्रदेश और सोमेश्वर की जनता ने मायके में बेटी को सम्मान दिया है अगले पांच सालों में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। महिलाओं के लिए काम करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकें , बच्चों को सेहत , शिक्षा और सुरक्षा के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करना ही मेरा लक्ष्य है।

-रेखा आर्या , कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

पहाड़ की खेल प्रतिभाओं को निखार रही उत्तराखंड सरकार –

महाराणा प्रताप खेल छात्रावास सहित तमाम गर्ल्स हॉस्टल को संवारने का फैसला

स्पोर्ट्स हॉस्टल में खाने और सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का फैसला

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में तैयार किये 50 मिनी स्टेडियम

खेल विभाग प्रदेश में तैयार करेगा 35 नए मिनी स्टेडियम

एससी / एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए 50 लाख स्वीकृत

मंत्री रेखा आर्या की ये हैं कुछ खास और बड़े निर्णय/उपलब्धियां

❖4000 बच्चों को ऑनलाइन दी गयी ढाई करोड़ की धनराशि

❖सुनियाकोट-मटेला मोटरमार्ग के लिएकुल 129.00 लाख धनराशि जारी कराया

❖पीआरडी जवानो को साल में कम से कम 300 दिन का रोजगार देने का फैसला

❖आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय बढ़ाने का फैसला

❖राशन कार्डों के दुरुपयोग पर "अपात्र को ना ,पात्र को हाँ"अभियान ने लगाई रोक

❖पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (P.F.M.S) सिंगल नोडल अकाउंट GOV. पोर्टलसे भुगतान करने काफैसला

❖12. 58 लाख डिजिटल राशन कार्ड बांटे गए जुलाई तक 100 फीसद का लक्ष्य

❖61 हज़ार बेटियों को मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभग्रेन एटीएम वाला तीसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड विश्व खाद्य योजना में लिया फैसला

❖पहाड़ के राशन डीलरों की व्यावहारिक समस्याओं का किया समाधान

❖खाद्य विभाग के नए टोल फ्री नंबर से मिली आम नागरिकों को सुविधा

❖अनाज घोटाले के आरोपी अफसरों पर सख्त कार्यवाही

❖1,84,142अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला

❖गेंहू खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला

❖अल्मोड़ा में बालिका छात्रावास को बनाए जाने का फैसलावात्सल्य योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को शपथ पत्र के ज़रिये देने का फैसला लिंगानुपात बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण अभियान पर जोर रणजी मैच की हार पर उठे विवाद की जांच कराने का लिया फैसला

❖फुटबाल खिलाड़ी हेमराज जौहरी की प्रतिभा निखारने का फैसला

वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में आयुर्वेद विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 253 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में, स्क्रीनिंग परीक्षा सम्पादित

71 आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों को नियुक्ति प्रक्रिया प्रचलन में, काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक के 13 पदों पर नियुक्ति

राज्य में 70 आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना कर संचालन प्रारम्भ

इस वर्ष 230 आयुष आयुष हैल्थ एवं वैलनेस केन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार से बजट की स्वीकृति

राज्य के 75 चयनित स्थलों एवं सभी आयुष चिकित्सालयों में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन

हल्द्वानी में 50 शय्यायुक्त आयुष चिकित्सालय की स्थापना का कार्य पूर्ण

प्रत्येक जनपद में कोविड रोगियों को त्वरित परामर्श हेतु आयुष हेल्पडेस्क की स्थापना

जनसामान्य में आयुष रक्षा किट व बाल रक्षा किट का वितरण

श्री पुष्कर सिंह धामी
मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड

हिंदी दैनिक **न्यूज़ वायरस**

देहरादून, मंगलवार, 05 जुलाई, 2022

विकल्प रहित संकल्प

उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

PTCUL

पिटकुल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

अनिल कुमार
प्रबंध निदेशक

- वर्ष 2021–22 में विद्युत पारेषण उपलब्धता 99.55 प्रतिशत रही है, जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मानकों (98 प्रतिशत) से अधिक है।
- वर्ष 2021–22 में पारेषण हानियां 1.01 प्रतिशत रही है, जोकि राष्ट्रीय मानकों से कम है।
- 220 के0वी0 डबल सर्किट व्यासी–देहरादून लाईन (71 सर्किट किमी0) लाईन को दिनांक 13.04.2022 को ऊर्जीकृत किया गया जिससे जनपद एवं आसपास के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है।
- ए0डी0बी वित्त पोषित ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण एवं विस्तारीकरण करने के लिए पारेषण तन्त्र की 10 परियोजनाओं हेतु डी0पी0आर0 तैयार की गयी है। उक्त प्रस्तावित परियोजनाओं के अर्न्तगत 08 नग 400 के0वी0, 220 के0वी0 एवं 132 के0वी0 उपसंस्थान क्रमशः लण्ढौरा, मंगलौर, सेलाकुई, लौहाघाट, आराघर (देहरादून), धौलाखेड़ा, खटीमा एवं सरवरखेड़ा को वर्ष 2023–24 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित उपकेन्द्रो के पूर्ण होने पर 1330 एम0वी0ए0 पारेषण क्षमता की वृद्धि होगी।
- तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्री बद्रीनाथ धाम के लिये विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में एक ही स्रोत के सापेक्ष वर्तमान में 03 स्रोतों से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु परियोजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अतः वर्तमान में 02 वैकल्पिक स्रोतों से श्री बद्रीनाथ धाम के लिये विद्युत आपूर्ति की जा सकती है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में पिटकुल द्वारा **रू0 33.00 करोड़ (रू0 तैंतीस करोड़ मात्र) (अंतरिम)** का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

दैनिक न्यूज़ वायरस

विकास के 100 दिन

उत्तराखंड की धामी सरकार में डॉ धन सिंह रावत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें शिक्षा , स्वास्थ्य और सहकारिता जैसे बेहद अहम विभाग की ज़िम्मेदारी दी गयी है। लिहाज़ा मंत्री पद का कार्यभार संभालते ही डॉ धन सिंह रावत ने लीक से हटकर कुछ नए फैसले लिए हैं। वे अपने कई फैसलों को लेकर चर्चा में भी रहे। स्वास्थ्य , शिक्षा और सहकारिता की योजनाओं को बीते 100 दिनों में मिली उपलब्धियों को आइये डालते हैं एक नज़र -

चिकित्सा शिक्षा में लिए गए बड़े निर्णय / योजना

नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में उद्योगों की मांग के मुताबिक पाठ्यक्रम तैयार करने का फैसला

कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर देने का फैसला

कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे कर्मियों के समायोजन का फैसला

राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 23 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया बनाने का फैसला

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीनगर के बस स्टेशन को मेट्रोपोलिटन शहरों की तरह बनाने का फैसला

डीजी लॉकर के माध्यम से छात्र-छात्राओं को डिग्री उपलब्ध कराने का फैसला

परीक्षा आयोजन 40 दिवस जबकि परीक्षा परिणाम 30 दिवस की अवधि करने का फैसला

शैक्षिक कैलेंडर लागू करने, निर्माण कार्यों को तय समय अवधि के अंतर्गत पूरा करने का फैसला

पी.जी.आई. चंडीगढ़ एवं उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा के बीच एकेडमिक एवं शोध कार्यों को मिलकर करने का फैसला

दून मेडिकल कॉलेज में 'सोटो' की स्थापना का फैसला

मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर, हरिद्वार में तेज़ी से हो रहा निर्माण कार्य

स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाने के अहम निर्णय

राज्य के अनाथ बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनाने का फैसला

जिला अस्पताल, संयुक्त ,प्राथमिक ,बेस अस्पतालों में IPHS मानकों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश

कोरोनेशन अस्पताल में आईसीयू संचालन के लिये 10 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति का फैसला

एनएचएम के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर हायर करने का फैसला

राज्य में एमबीबीएस डॉक्टर की कमी को जल्द से जल्द दूर करने का फैसला

राज्य में मरीजों को बेहतर और तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर फोकस

स्वैच्छिक रक्तदान पंजीकरण में उत्तराखंड ने बनाया कीर्तिमान

प्रदेश में 4063 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान क्र बनाया देश में कीर्तिमान

गैरकानूनी तरीके से चल रहे निजी अस्पताल तथा नर्सिंग होम के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश

प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिये,

जांच के दौरान निजी अस्पताल के मानक पूरे नहीं पाये जायेंगे उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

निजी अस्पतालों के संचालन संबधी क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव

राजकीय अस्पतालों में 207 के स्थान पर 258 जांचे निःशुल्क किये जाने का फैसला

देश और प्रदेश के डॉक्टरों व स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सुझावों से एक वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने का फैसला

प्रेमनगर संयुक्त अस्पताल के विस्तारीकरण कर पूर्व विधायक हरबंश कपूर के नाम पर रखने का फैसला

आपात स्थिति में गंभीर मरीज़ों को हेली सुविधा से अस्पताल पहुँचाने का फैसला

आपदा में एयरलिफ्ट कराने के लिए प्राइवेट कंपनी से करार करने का फैसला

जिला और उप जिला अस्पतालों को चार महीनों में दुरुस्त करने का फैसला

राज्य के हर अस्पताल में मरीजों को निशुल्क इलाज, दवा और जांच की मिली सुविधा

गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने और घर ले जाने के लिए भी निशुल्क मिली सुविधा

शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में लिए गए बड़े फैसले

संस्कृत, ज्योतिष और कर्मकांड के अध्ययन व शोध को बढ़ावा देने का फैसला

स्कूलों में छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना पर काम तेज़

सुगम और दुर्गम में तैनात शिक्षकों के तबादले में आई पारदर्शिता

हरियाणा के साथ बैठक कर शिक्षा की बेहतरी के प्रयासों व नवाचार का फैसला

निजी स्कूलों को पर्वतीय क्षेत्रों में खोलने पर जमीन और अन्य सुविधाएं देने का फैसला

शिक्षा के अधिकार के तहत तहसील स्तर पर कैंप लगाकर आय प्रमाण पत्र बनाए जाने का फैसला

कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर अनिवार्य रूप से प्रवेश देने का फैसला

डायट, अटल आदर्श विद्यालय एवं नवोदय विद्यालयों की पृथक नियमावली बनाने का फैसला

शीघ्र पैक्स सचिवों की नियमावली को अंतिम रूप देने का फैसला

प्रत्येक विकासखण्ड में ADO सहकारिता को तैनात करने का फैसला

उ0प्र0 के साथ विभाग की परिसंपत्तियों का बंटवारा किये जाने के लिए तेज़ हुई कार्यवाही

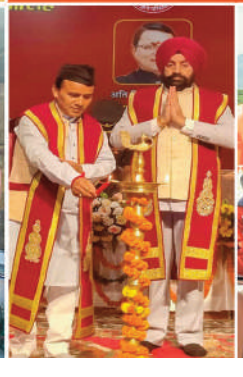

दैनिक न्यूज़ वायरस

दैनिक न्यूज़ वायरस

Empanelment with:
DAVP, Govt. of India, New Delhi
NFDC, Govt. of India, New Delhi
DIPR, Govt. of Uttarakhand, Dehradun
DIPR, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow

Film Productions

TV Spot, Documentries,
Scheme Launching Film
Departmental AV Film
and AV Presentations

Branding Solutions

All New Media Solutions
Advertisement Solutions
Event Management
Launching Program Management
Departmental Fair and Exhibition

NEWS

YouTube News Channal
News Portal
Hindi Daily Newspaper

Mohd Saleem Saifi
CEO/Group Editor

NEWS VIRUS

News Virus Network Private Limited

Dehradun | New Delhi | Lucknow | Meerut

E-mail: tvnewsvirus2021@gmail.com | Web: www.newsvirusnetwork.com